[Shri K. Natwar Singh]

there, stay at home They built the country, they contributed so much to it for the last 120 years, and they have a claim there. So, while I appreciate the pressure upon them and their difficulties, if they were to leave in great haste, then they would perhaps give a green signal to the coup leaders to entrench themselves for all times and to introduce the Constitution which would put the Indian community in a minority, because then they will say, in any case we are in a majority, because a small number can tilt the balance That is why I am hoping that our stout-hearted people, the people of Fiji, will fight for their democratic rights With whatever help that we can give and the world community can give, I think that the fact that the Commonwealth has disapproved of the coup and taken the stand on terminating Fiji's membership must have heartened them a great deal. If I have left any particular question unanswered, I am sorry. I have tried to give the overall picture. I merely want to say that the question of our appearing to the inactive does not arise I think India is one country which has been most active from the first day in this regard, bilaterally, within the Commonwealth, in the United Nations and even among the non-aligned countries. The fact is that it has not allowed the subtle propaganda. I mentioned to drive a wedge between India and Africa by saying that the Indians are settlers. The term was actually used in one conversation. It was said, "How does it differ? The whites are settlers in Africa. You are settlers in Fiji." It sounds very simplistic We have been able to combat them, and combat them very effectively.

I will certainly keep the House informed about further developments. We are having detailed discussions in the Ministry We have the benefit of our High Commissioner who has lived through this since the 14th of May. He came here only a few days ago If the need arises, I will certainly place further facts before the House.

SHORT DURATION DISCUSSION ON DROUGHT AND FLOOD SITUATION IN DIFFERENT PARTS OF THE COUNTRY

श्री शंकर सिंह वाघेला (गुजरात) : वाइस-चेयरमैन सर, देश में कई राज्यों में इस सदी का...

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) समय बहुत कम है।

श्री शंकर सिंह वाघेला आप चाहें तो आप चर्चा बंद कर दीजिये।

I am least concerned. The Govt has allowed this discussion. It is very important. All parts of the country are suffering from drought and floods, Sir

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) मैं आपको ना नहीं कहता हूं। इस पर 18 मेम्बर बोलने वाले हैं, आप बोलिये।

SHRI SHANKER SINH VAGHELA : I have to initiate the discussion, Sir, with full details.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA (Gujarat) : Half-an-hour was taken on Fiji. So, you extend this half-an-hour

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) . Yes, positively

श्री शंकर सिंह वाघेला वाइस चेयरमैन सर, सारे देश के कई राज्यों में इस सदी का सबसे भीषणतम और भयंकर अकाल सूखे के कारण पड़ा हुआ है और शेष बचे हुए राज्यों असम, बिहार और बंगाल में बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ है इस पर अल्पकालिक चर्चा की जो आपने अनुमति दी है इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए बड़े भारी दुखी हृदय से इस सूखे और बाढ़ की चर्चा प्रारम्भ करता हूं। महोदय, यह चर्चा सिर्फ चर्चा न रहे। हमारी भारत सरकार इस चर्चा में जितने भी सदस्य भाग लें और वे जो सुझाव व्यक्त करें उन सुझावों पर अमल करे, उनका अमलीकरण हो। देश के कैटल बिना पानी के और घास के मर रहे हैं, मजदूरों को

उनकी पूरी तनख्वाह नही मिल रही है, उनको खाना नही मिल रहा है। उनको खाना मिले, तनख्वाह मिले इसके लिये अगर सरकार काम करे तो सरकार का बडा आभारी हूंगा। कृषि मंत्री ने शुक्रवार को यहा जवाब दिया पता नही कैसे उन्होंने यह जवाब दिया, किस इन्फर्मेशन के आधार पर जवाब दिया कि गुजरात में कोई कैटल नही मरे है। इस तरह का जवाब देने में क्या उन्हें संकोच नही हुआ? महोदय, अकेले गुजरात में करीब 20 हजार कैटल पर डे मरते है बिना पानी के, बिना घास के। राजस्थान में 25 हजार पर डे मरते है और दूसरे राज्यो में अगर 5-10 हजार हम गिन ले तो हमारे देश में पर डे 50-55 हजार कैटल बिना पानी और बिना घास के मर रहा है। मंत्री महोदय ने पता नही कैसे कहा कि गुजरात में कैटल नही मरे है। मैं श्री अरुण सिह जी का आभार व्यक्त करता हूं जो उन्होंने इस मामले में इंटरफेयर करके सही बात बताई। आशा है कि मंत्री जी अब अपने जवाब में इसको जरूर सुधारेंगे, ऐसी मैं उनसे अपेक्षा करता हूं। सर, मेरे पास कच्छ के बारे में यह पम्फलेट है। इसमें उनके अस्थि पंजर के साथ मरते हुए पशुओ के फोटो है। आशा करता हू कि मंत्री महोदय इसको देखेंगे और इस बारे में निर्णय लेते समय इसका प्रयोग करेंगे। सर, हमारे गुजरात, राजस्थान में यह तीसरा चौथा अकाल है। इस अकाल में बहुत से लोग बेकार हो गये है। तकरीबन गुजरात में 25 लाख मजदूर बेकार है। इस भयंकर अकाल में जो गरीब लोग है उनके लिये राहत की व्यवस्था पूरे देश में, चाहे बाढ के कारण यह स्थिति हो या चाहे सूखे के कारण हो केन्द्रीय सरकार की ओर से तथा राज्यो की ओर से सही राहत की व्यवस्था नही है। यह दुख के साथ मुझे कहना पडता है। अकाल के लिए मैं सिर्फ प्रकृति या कुदरत को ही दोष नही देता इसके साथ-साथ मानवसृजित अकाल और बाढ़ की समस्या है। इसके लिए मैं यह जरूर कहूंगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे नेताओ ने कहा था कि हमारे देश में घी और दूध की नदियां बहेंगी लेकिन जब यहा पर कम्युनल रायट्स होते है तो खून की नदियां बहती है। हमने कहा था वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलाम, सफलाम् मलयज शीतलम् शस्यशामलम्। लेकिन आज बिना पानी, बिना घास और बिना अनाज मरते हुए लोग और पशु आप देखेंगे, क्या दुर्दशा की है आपने भारत माता की? मैं यह पूछना चाहता हू यह क्या दुर्दशा आपने यहा कर दी है? आप इस देश की सत्ता में कितने सालो से आए है इतने सालों से आप सत्ता में बैठे हुए है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज की जो हालत है इसके लिए पंडित जवाहर लाल नेहरु जी, इंदिराजी से लेकर राजीव गांधी तक पूरा नेहरू वंश इसके लिए जिम्मेदार है। **(व्यवधान)** देश की इस हालत के लिए यह जिम्मेदार है **(व्यवधान)** हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यहा पर 80% जनता कृषि पर आधारित है **(व्यवधान)** स्व नेहरू जी ने इसके अलावा पंचवर्षीय योजनाओ के पीछे, कम्युनिस्ट कंट्रीज के पीछे आपने देश को लगाया। देश को खत्म करने की जिम्मेदारी आप पर है। देश में जिस ढंग से आपने गलत नीतियो का इम्पलीमेंटेशन किया उसके लिए आप जिम्मेदार है। आप 21वी सदी में जाने की बात करते है। **(व्यवधान)** आज भी यही रूलर्ज बैठे है **(व्यवधान)**

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल (गुजरात) इसमें पोलिटिक्स क्यों लाते हो। जरा ठीक तरह बोलो।

श्री शंकर सिंह वाघेला : हम जो बात कहेंगे सही कहेंगे इसमें कोई पोलिटिकल एंगल नही होगा। **(व्यवधान)** 21वी सदी में जाने की बात करते है **(व्यवधान)** हम 21वीं सदी में जाने की बात करते है आज तक हमने साइंस और टेक्नोलोजी का उपयोग क्यो नही किया? इजराइल और हमारा देश एक साथ आजाद हुए। आप इजराइल को देखिए। अकेले बारिश के पानी का उपयोग इजराइल 95% अपनी खेती की व्यवस्था के लिए करता है। 95% पानी का उपयोग कितना बडा उपयोग होता है **(व्यवधान)** आज हम पर्यावरण की चिन्ता करते है। अगर पर्यावरण की चिन्ता की होती तो कितने सालों से करनी चाहिए थी। कितने सालो से हमारे जंगल हिमालय पर्वत में काटे जलाये जा रहे है। श्रीमन्, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार मैं शिमला जा रहा था तो उस समय जंगलो में आग लगी हुई थी और जब मैं वापिस आया तब भी जंगलो में आग लगी हुई थी। क्या आपके पास आग बुझाने का कोई आधुनिक उपाय है? आप

जंगल कटवाते हैं। कांग्रेस (आई.) के लोग, कार्यकर्ता जंगल कटवाते हैं क्योंकि इनमें उनकी भागीदारी होती है (व्यवधान) पर्यावरण के इम्बेलेंस के कारण ही आज सूखे की भयंकर समस्या है इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। श्रीमन्, जंगलों और वन सम्पदा का वर्षा से सीधा सम्बन्ध है और वर्षा पर्यावरण पर ही आधारित है। अगर प्लानिंग ऐसा किया होता, देश में स्टाप डैम और चेक डैम का जाल बिछा होता, पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी के साथ-साथ पानी नीचे परकोलेट होने की पूरी व्यवस्था हो सकती थी। लेकिन हमने यह व्यवस्था नहीं की। आज पर्यावरण और जंगलों का विनाश हो रहा है। श्रीमन्, हमारे देश में 1931 में 30% जंगल थे। 1951 में 23% जंगल बच गये। आज 1987 में सिर्फ 8% जंगल बचे हैं। हर साल जंगल कटवाने का रेश्यो इतना बढ़ता चला गया कि आज 1987 में केवल 8% जंगल बचे हैं। हर साल 10% जंगल कटते हैं जबकि 1931 में हमारे देश में 30% जंगल थे। यदि जंगल काट दिये जाएंगे तो वर्षा कहां से आएगी? इन जंगलों को कटवाने के आप जिम्मेदार हैं। इसलिए आपको जंगल बढ़ाने की चिन्ता करनी चाहिए। जंगलों को काटने की वजह से सारा पर्यावरण इम्बेलेन्स्ड हो गया है। इन जंगलों की वजह से उत्तर पश्चिम से जो ठंडी हवाएं आती हैं उससे बारिश नहीं होती है उस पवन को जंगल रोकते थे। लेकिन दुःख की बात यह है कि जंगल काट दिये गये हैं। हबीब अंसारी ने इसमें कहा है कि वनस्पति और वर्षा का सीधा आपस में सम्बन्ध है। सूखा और बाढ़ के लिए "अलमीनो" नाम का गरम पानी का प्रवाह पेसिफिक महा-सागर में है। गरम पानी का यह "अलमीनो" प्रवाह इसके लिए जिम्मेदार है। बाढ़ और सूखा दोनों के लिए जिम्मेदार है। बाढ़ से हमारे देश की उपजाऊ जमीन 600 टन पानी में बह जाती है। नदियों को तोड़कर बाढ़ आती है। वाटर ग्रिड की जो बात है उसको आप एक्जीक्यूट करिये। जहां बाढ़ आती है वहां के पानी को डैम में रोके। दूसरी नदियां हैं, काश्मीर में झेलम है, व्यास है, ये नीचे आ सकती हैं, बाकी नदियां नीचे आ सकती हैं। वाटर ग्रिड की बात अभी नहीं हो सकती है तो बाढ़ को डैम्स से रोके और जहां सूखा हो उस एरिया में पानी डालिये। वाटर ग्रिड देश को बचाएगा। सेंटर जितना जल्दी इसका प्रयोग करेगा मैं समझता हूं कि उतनी जल्दी ही देश को आप राहत पहुंचाएंगे। यह तो करें लेकिन हमारे राजस्थान और गुजरात के लिए पाकिस्तान से प्रेम करिए। पाकिस्तान की सिन्ध नदी का पानी बचा हुआ है। बहुत जल्दी कच्छ और राजस्थान में आ सकता है। मेहरबानी करके पाकिस्तान से बातें करें। बिना पानी बिना फाडर बार्डर का इलाका भर रहा है ह्यूमन बेस के साथ, मानवता के आधार पर पाकिस्तान से बात करके आप देश को, गुजरात को, राजस्थान को पानी दिला सकते हैं।

आप कृत्रिम वर्षा का प्रयोग करिये। कई जगह बिल्कुल बादल छाये होते हैं जिसमें पानी होता है। लेकिन वर्षा का प्रयोग टाइम पर नहीं होता है। कृत्रिम वर्षा से बादलों से पानी गिरे तो भी फाडर और पीने के पानी की समस्या हल्की हो सकती है। अकाल और बाढ़ होती है तो कौन मरता है। सबसे पहले गरीब मरता है, किसान मरता है, गरीब किसान मरता है, किसान पर जिंदा रहने वाला खेत मजदूर मरता है, खेती पर जीने वाला कैटल मरता है। जो भी व्यवस्था होनी चाहिए वह आज तक हमने नहीं की है।

सर, हमारे देश में हमारा किसान बैल को बाप कहता है, भैंस और गऊ को मां कहता है। उस मां और बाप को अपनी नजरों के सामने मरता देखने से पहले खुद मरना चाहता है। हमारे गुजरात में एक किसान ने अपने दो बैल कैटल कैंप में रखे। एक दिन वह अपने बैल की हालत देखने गया तो बैल रो रहे थे, रोते हुए बैलों को देखा नहीं गया तो घर ले गया और जहर पिलाकर बैलों को मार डाला फिर खुद भी जहर पीकर मर गया। यह हालत अकाल की है। अकाल क्या है देखना है तो आइये राजस्थान और गुजरात में। एक-एक, दो-दो, पांच-पांच हजार के बैलों को किसान उनके सर पर टीका लगाकर करके छोड़ देते हैं और कहते हैं कि जाओ ऊपर भगवान है नीचे धरती। सर, रास्ते में कसाई लोग पकड़कर इन बैलों को ले जाते हैं और काट डालते हैं। इसका प्रूफ आपको चाहिए? गुजरात में मटन और बीफ 15 से 17 रुपये किलो बिकता था, आज वह एक या दो रुपये किलो मिलता है वह भी उधार से भी मिल जाता है। आपको पता नहीं है क्या हो

[श्री शंकर सिंह वाघेला]

रहा हूँ। पशुओं की रक्षा आप नहीं करते हैं . . . (व्यवधान) और भी आगे कहूंगा कि आपने इन्सानों को पीने के लिए पानी नहीं दिया है। हमारे शहर को आल्टरनेटिव दिन में 20 मिनट पानी मिलता है। आपके बाथ-रूम्स में कितना पानी बहता है। लेकिन वहां 20 मिनट पीने का पानी, तीन दिन में एक दिन। यह तो इन्सान की बात हुई लेकिन कैटल के, पशुओं के पीने के पानी की क्या व्यवस्था आपने पूरे देश में की है? इन्सानों को पीने पिलाने के लिए जो टैंकर्स होने चाहिए वे भी पूरे प्रोवाइड किये हैं? हमारी जो केन्द्रीय टीम्स जाती हैं, पी. एम. का दौरा होता है तो अच्छी-अच्छी जगहों को दिखाते हैं। इसीलिए जो केन्द्र की मदद मिलनी चाहिए वह कम मिलती है। इसलिए केन्द्रीय टीम को सही एरियाज दिखाने चाहिए।

प्रधान मंत्री का दौरा होता है। प्रधान मंत्री जी जितना खर्चा दौरे पर करते हैं, इतना खर्चा राहत में दें, टी वी में इतना ड्रामा पगड़ी पहनने का न दिखाया जाये कि यह किया, वह किया, पोलिटिकल स्टंट न हो तो ज्यादा अच्छा हो (व्यवधान) पी. एम. गुजरात में आये और गुजरात को 500 टन घास दी। यह गुजरात राज्य के साथ बड़ा मजाक है। प्राइम मिनिस्टर आते हैं और 500 टन भूसा देते हैं। खर्चा कितना होता है? 4-5 करोड़ का दौरे का खर्चा और भूसे का कितना खर्चा है सर? सर नागालैंड में चुनाव है, नागालैंड में अकाल नहीं है। जबकि नागालैंड में अकाल नहीं है आप नागालैंड में सूखे की व्यवस्था करने जा रहे हैं। वहां के लोग बोलते हैं कि हमें मदद नहीं चाहिए।

राहत की व्यवस्था में मैं आपसे जरूर प्रार्थना करूंगा कि आप कोई साइंटिफिक बेस रखिये। हमारे गुजरात में 8-9 लाख लेबर काम करती है, आपने 66 करोड़ रुपये उनके लिए दिये। राजस्थान में आठ लाख कुछ मजदूर काम करते हैं, इनको इससे डबल रुपया आपने दिया। उत्तर प्रदेश में इससे कम लेबर काम करती है, पर इसको भी ज्यादा रुपये दिये। तो राज्यों को मदद देने का आधार, रुपया देने का आधार आपका क्या है? कोई ऐसी वैज्ञानिक पद्धति आप उसमें प्रयोग करिए जिससे सूखे और बाढ़ की तीव्रता के आधार पर . . . (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : This is a point.

श्री शंकर सिंह वाघेला : उसके आधार पर आपको मदद करनी चाहिए। हमारे सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके आप जानते हैं। वहां पानी धरती के नीचे से लाने का कोई सोर्स नहीं है। पांच सौ करोड़ रुपये की एक नर्मदा पाइप-लाईन की योजना की तीन साल से बात चल रही है। अभी तक वह प्रोपोजल स्टेटर के पास नहीं आई है। आप भी वहां से बात करके लोगों को पीने के पानी की तीन साल से बात न करते हुए पांच सौ करोड़ को या जो भी सुविधा दे सकें, एज अर्ली एज पासिबल वह इम्पलिमेंट हो, ऐसी मैं जरूर आपसे प्रार्थना करूंगा। इसी के साथ केनेडा के टेरा (TERA) टैंक्स हैं, जिनमें पानी भर कर के बहुत जगह दूर ले जा सकते हैं, बैगस में, ट्रक्स में डाल कर इसका भी प्रयोग करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। सस्ता पड़ेगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : अब आप कनक्लूड कीजिए। पंद्रह मिनट हो गये हैं।

श्री मीर्जा इर्शादबेग (गुजरात) : आप पोलिटिकल ज्यादा बोल रहे हैं।

श्री शंकर सिंह वाघेला : मैं सही बोल रहा हूं जिसका पोलिटिकल प्रयोग हो रहा है। सर, अकाल में पोलिटिकली तो यही लोग बात करते हैं। हमारे मुख्य मंत्री के पैर खींचते हैं। आप ही लोग हमारे सी एम के पैर खींचते हैं। हमारे मुख्य मंत्री कुछ करते हैं, तो आपसी युद्धबंदी में उनके पैर खींचने वाले लोग वही हैं, हम तो नहीं होते हैं।

हम तो पूरे गुजरात में अकाल न्याय यात्रा के हिसाब से मदद करने जा रहे हैं।

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल : हां, हां, बहुत मदद कर रहे हैं।

श्री शंकर सिंह वाघेला : सर, इससे होने वाला क्या है? कि लेबर को जो काम मिलना चाहिए, हमारी सरकार ने कहा कि 11 रुपये मिलेंगे--पर ऐसे लोग हैं जिनको साठ पैसे हर रोज मिलते हैं। दूसरे हर रोज नहीं तो हफ्ते में इनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। डेढ़-डेढ़ महीने तक इनको तनख्वाह नहीं मिलती। तो वह खायेगा क्या?

[श्री शंकर सिंह वाघेला]

इस अकाल से जो पूरे देश का अर्थ तंत्र है, वह टूट जाएगा। अर्थ तंत्र चौराहे पर खड़ा है। हमारी इकानमी कृषि बेस्ड इकानमी है। इस कृषि बेस्ड इकानमी का पूरा ध्यान नहीं दिया। आज आपने रुपये की कीमत दस पैसे कर दी है, उस दस पैसे के एक रुपये की क्रय-शक्ति कितनी रही ? कृषि का आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसमें 15 करोड़ टन अनाज की बात, मान्यवर कृषि मंत्री जी, 12 करोड़ टन अनाज भी आप इकट्ठा करेंगे, तो बहुत अच्छा होगा।

अब आपके एफ सी आई. की क्या हालत है। एफ सी.आई. की चिंता करिए। लोगों को भूखों मारने में आप जिम्मेदार न हों। एफ.सी.आई. के गोदामों में माल नहीं है। हमारे सप्लाई मिनिस्टर कहते हैं कि गुजरात को गेहूं सप्लाई करेंगे। गुजरात सरकार गेहूं की डिमांड करती है। लेबरर्ज को गेहूं देते थे, पर आज नहीं देते हैं। न सिर्फ गेहूं बल्कि पोषक आहार लेबर को दिया जाना चाहिए। सिर्फ गेहूं खाकर वह नहीं जिएगा, उसको तेल, गुड़, प्याज भी चाहिए। आप उसको पोषक आहार दीजिए जिससे व काम कर सके वरना उसके आंखो से अंधा होने की भी पूरी संभावना है। इसकी रिपोर्ट भी है। यह जो कृषि खाद होगी, इससे कैटल कट जाएंगे, परिणामत: दस रुपये किलो दूध नहीं मिलेगा, सब्जी चखने के लिए नहीं मिलेगी, खाद्य तेल का भाव इतना बढ़ गया है और प्राईस राईज 8.6 प्रतिशत हो रहा है। Double Digit Inflation. आप इम्पोर्ट करेंगे इस सप्लाई को मैंटेन करने के लिए, तो आठ हजार करोड़ रुपये का तो आपका ट्रेड बेलेंस का घपला है, आठ हजार करोड़ रुपये का डेफिसिट फाइनेन्स है, आप देश को किस हालत में ले जायेंगे? देश की इकानमी कहां जाएगी? हमारा जो उत्पादन कम होगा, 8 परसेंट कम होगा, 5500 करोड़ रुपये का, इससे भी नुकसान होगा और आगे भी देखना है कि यह सूखे और फ्लड में करप्शन न हो, कर्मचारी और पोलिटिकल लोग और अनसोशल एलीमेंट्स, यह लोग इसमें मिल कर के जो गड़बड़ी करते हैं, वह न हों।

इसके साथ ही हर कैटल के लिए पांच रुपये सब्सिडी देनी चाहिए और न सिर्फ उनके लिए जो कैटल कैम्प में हों, वहां, लेकिन जिस किसान के घर पर कैटल हों, उसको भी कैटल के लिए पांच रुपये सरकार को देना चाहिए क्योंकि वह कैटल कैम्प में नहीं रखता है, तो कोई कसूर नहीं है। उसको भी सरकार को मदद करनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ कुछ रिकोमेंडेशंस करना चाहूंगा जिससे कि यह पोलिटिकल मामला न हो। इसलिए आपसे प्रार्थना है, माननीय मंत्री जी से भी, कि देश में राष्ट्रपति महोदय की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सूखा राहत समिति का गठन हो, जिसमें सब पोलिटिकल लोग, सोशलाजिस्ट्स, इकानोमिस्ट्स तथा इंजीनियर्ज ऐसे लोग हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। देश को लाभ होगा। दूसरे देश की अकाल राहत संहिता अंग्रेजों के जमाने से है जिसे अब तक चेंज नहीं किया गया। इसलिए इस अंग्रेजी के जमाने से बनी हुई अकाल राहत संहिता की वर्तमान संदर्भ में उपयोगिता बिल्कुल नहीं है। अत: केन्द्रीय स्तर पर इसमें संशोधन करके आज की आवश्यकता के अनुरूप इसको अद्यतन अर्थात अप टू डेट किया जाए। साथ ही सूखा और बाढ़ तथा अन्य जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को सहायता देने की प्रणाली पर पुनर्विचार किया जाए और आंशिक सहायता या योजना का अग्रिम न देते हुए प्रभावित प्रदेशों को शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाए। योजना में से कुछ काटा नहीं जाना चाहिए बल्कि पूरी ग्रांट देनी चाहिए।

उप-सभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : यह बात आप सब से पहले बोले होते तो कितना अच्छा होता।

श्री शंकर सिंह वाघेला : सरकार को ऐसे गावों में तुरन्त पशु-शिविर खोलने चाहिए जहां पर चारे की कमी हो और जहां पर लोग अपने पशुओं को खिलाने में असमर्थ हो वहां पर सरकार कैटल कैंप लगाए। समाज सेवी संस्थाएं काफी सुविधाएं दे रही हैं इसके लिए तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन सरकार को भी समय पर सहायता देनी चाहिए जिससे इसके लिए भी कोई रास्ता

[श्री शंकर सिंह वाघेला]

निकले। सरकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम के अधिकार को सैद्धांतिक रूप में स्वीकार करके अकाल पीड़ितों को रोजगार उपलब्ध कराए और राहत कार्यों की जांच करें ताकि लोगों को अनाज, खाने का तेल, मिट्टी का तेल और आवश्यक वस्तुएं नियमित रूप से उपलब्ध हों। इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। पानी के लिए भी जहां पर भूमिगत जल स्तर बिल्कुल नीचे चला गया है और पेयजल की व्यवस्था नहीं है वहां पर कोई दीर्घकालीन उपाय किए जाएं जिसके लिए विशेषज्ञों की राय लेकर कार्यवाही की जाए। जिससे दूषित पेयजल पीने से लोगों में भयंकर बीमारियां न हों। इसके लिए भी सरकार को चिंता करनी चाहिए। पशुओं को फौडर और आहार देने के लिए विदेशों से आयात किया जाए। आप फौडर को इंपोर्ट करिए और घास को जो कि पशुओं का आहार है ताकि अच्छी नस्ल के पशु नष्ट न हो जाएं। इसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए।

आखिरी बात, किसानों को बचाने के लिए उनका भू-राजस्व ही माफ करना काफी नहीं होगा, बल्कि जहां पर तीन वर्ष से लगातार सूखा है उन क्षेत्रों के किसानों के सब प्रकार के सरकारी और सहकारी कर्जों को मुआफ किया जाना चाहिए। फसल बीमा योजना को व्यक्तिगत आधार पर सारे देश में तत्काल लागू किया जाए। इसी प्रकार पशु बीमा योजना को भी लागू करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए। इन शब्दों के साथ, इस सब के लिए कोई पोलिटिकल एंगल न रखते हुए, चुनाव हो या न हो, देश में जहां भी सूखे और बाढ़ से प्रभावित लोग हों, एक साइंटिफिक आधार लेकर जहां अकाल की तीव्रता है वहां पर केन्द्र सरकार अपनी टीम को भेजे और वह केवल अच्छे इलाके ही न देखे बल्कि जहां-जहां वास्तव में अकाल है वहां पर वह जाकर पूरी स्टडी करे और स्टडी करके राज्य सरकारों ने जो मास्टर प्लान दिए हैं उसके अनुसार पूरे रुपये दिए जाएं जिससे कोई भी राज्य सरकार केन्द्र सरकार का कोई कसूर न निकाले, आभार व्यक्त करते हुए माननीय कृषि मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि इसका कुछ एक्सी- ——— करें। धन्यवाद।

श्री दरबारा सिंह (पंजाब) : सूखे की जो-जो अवस्था हुई है उसको सूखी अकाल से नाप-तौल न किया जाए।

उप-सभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) हां-हां, ठीक है। श्री मीर्जा इर्शादबेग।

श्री मीर्जा इर्शादबेग मान्यवर उपसभाध्यक्ष जी, हमारे गुजरात के ही माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे, लेकिन इनके साथ दिक्कत यह होती है कि उनकी और हमारी बातें तो कुछ-कुछ सही होती हैं, लेकिन उनकी प्रायरटीज और हमारी प्रायरटीज में थोड़ा सा फर्क पड़ता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री मीर्जा इर्शादबेग) नहीं-नहीं, उनका जो लास्ट पार्ट था, वह?

श्री मीर्जा इर्शादबेग इसीलिए कह रहा हूं, उनकी अग्रिमता दूसरी है। और पोलिटिकल प्रथम है। मान्यवर, फिर भी उनके कुछ सुझाव अच्छे हैं और मैं उनके साथ अपनी सहमति व्यक्त करता हूं और सदन के सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि यह एक प्राकृतिक आपदा है जिसका न सिर्फ सरकार बल्कि जनता और समाज के सभी वर्ग जब तक एक साथ मिलकर इसका मुकाबला नहीं करेंगे तब तक इस आपदा का सामना सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। मान्यवर, देश आज भयंकर सूखे तथा बाढ़ से ग्रस्त है और उसमें व्याप्त है। यह कहना जरूरी होगा कि इस बार का सूखा इस शतक की एक अभूतपूर्व घटना है। ऐसा सूखा पहले कभी नहीं हुआ है। लेकिन आज संपूर्ण मनोबल के साथ सरकार एवं जनता इसका प्रभावी मुकाबला कर रही है। इस भयंकर सूखे तथा बाढ़ का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष असर है कि जिसने खरीफ को, औद्योगिक क्षेत्र, ऊर्जा उत्पादन, सिंचाई तथा देश की आपूर्ति व्यवस्था को अपने दुर्भावपूर्ण असर से ग्रस्त किया है।

मान्यवर, 2854.45 लाख व्यक्ति तथा 1,639.84 लाख पशु इससे प्रभावित हैं, जिसकी मात्रा आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती है। देश के सिर्फ 37 प्रतिशत हिस्से में ही इस वर्ष बारिश सामान्य या अधिक रही और बाकी तमाम भूमि वर्षा से अतृप्त रही। खरीफ के अन्न-उत्पादन 90 मिलियन टन की अपेक्षा इस वर्ष सिर्फ 73

[श्री मीर्जा इर्शाद बेग]

मिलियन टन हुए हैं और मैं सरकार को बधाई दूंगा कि यह घटना सरकार रबी की मात्रा 76 मिलियन टन से बढ़ाकर उसको पूर्ण करना चाहती है। खाद्य-तेल में 9.9 लाख मीट्रिक टन को सरकार ने 538 करोड़ रुपये का तेल आयात करके पूरा करने की कोशिश की है।

मान्यवर, अभी उन्होंने कहा कि भावों में वृद्धि हुई है, लेकिन मैं सदन के सामने यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने भाव-वृद्धि को रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं, वह सराहनीय हैं और सितम्बर तक कंज्यूमर-गुड्स में होलसेल प्राइस में 1.4 प्रतिशत की गिरावट आई, जो सराहनीय है। वार्षिक-प्लान के बारे में अभी कह रहे थे वाघेला साहब कि प्लान में इससे एफेक्ट होता है। लेकिन मैं बधाई दूंगा सरकार को कि उन्होंने आर्थिक-नीतियों में वार्षिक प्लान की कटौती किए बगैर सूखे के लिए 1600 करोड़ रुपए की सहायता की योजना राज्यों के लिए बनाई, जो सराहनीय और अभिनदनीय है। इसी तरह रोजगार के जो साधन उपलब्ध कराने की और पेयजल की योजना है, खाने के तेल की, किसानों के लिए बीज-उर्वरक की विशेष योजनाएं उन्होंने बनाई हैं, उसके लिए वे अभिनंदन के पात्र हैं।

मान्यवर, इस विषम परिस्थिति में भी, जैसा उन्होंने कहा, मैं उनको जवाब देना चाहूंगा कि अर्थ-नीति को जो जानने वाले हैं, वे इसकी सराहना जरूर करेंगे कि इस विषम परिस्थिति में औद्योगिक विकास-दर 8 प्रतिशत की मात्रा में और विकास-दर 5 प्रतिशत की मात्रा में मेण्टेन करना एक सक्षम आर्थिक नीति का प्रमाण है। बाढग्रस्त इलाकों में सहायता देने के संबंध में राज्यों को 244 16 करोड़ की जो सहायता दी है तथा किसानों को बीज व उर्वरक की सहायता उपलब्ध कराई है इसके लिए सरकार सराहना की पात्र है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि बड़ी नदियों के पानी के जो बांध की योजनाएं हैं, उनको संपूर्ण करना है और इसका निवारण दीर्घकालिक योजना को सपूर्ण करने से हो सकेगा। सरकार को इस दिशा में सोचने की अत्यन्त आवश्यकता है।

मान्यवर, देश में आज सूखे से सबसे अधिक प्रभावी राज्य जो हैं, वे हैं गुजरात तथा राजस्थान। मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात में सरकार तथा प्रजा दोनों साथ मिलकर इस कुदरती प्रकोप का सामना आज दृढ़-मनोबल के साथ कर रहे हैं। सूखे के बारे में यह कहा जा सकता है कि यहां ही आसमान टूटा है। जहां आसमान टूटा हो वहां मानव का कोई साधन कारगर नहीं हो सकता। मानव अगर पैसा भी बिछा दे तो उससे कहीं भी जो चीज उपलब्ध है, वह समेट कर ला सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत-सी ऐसी बातें हैं जो हम उपलब्ध नहीं करा सकते हैं।

मान्यवर, मैं गुजरात के मुख्यमंत्री श्री अमरसिंह चौधरी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने पूरी क्षमता रखकर तमाम कार्यों को अपने हाथ में ले लिया और उसको तेज गति से निपटाने के लिए पूरा दृढ़ मुकाबला किया है। उसके साथ-साथ गुजरात की जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, मैं तो कहूंगा कि देश में ऐसी कम ही संस्थाएं हैं, उन तमाम संस्थाओं ने कोई भी पोलिटिकल दृष्टि न देखते हुए यह देखा है कि गुजरात के मवेशी, गुजरात के किसान, गुजरात के मजदूर और गुजरात के गरीब जो हैं, जो सूखे से प्रभावित हैं, यह एक मानवतापूर्ण बात है, जिसकी वजह से वे सारी की सारी संस्थाएं इसमें जुटकर आज सरकार का सहयोग कर रही हैं।

मान्यवर, मैं बधाई दूंगा अपने प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने बार-बार इन इलाकों में मुलाकात ली है लोगों से। मान्यवर प्रधानमन्त्री जी ने गुजरात में आकर उन असरग्रस्त इलाकों में गए, वहां के लोगों से मिले... प्रभावी लोगों से मिलकर उनकी बात को सुना है। अधिकारियों के साथ बैठकर बात की है। यहां आकर केन्द्रीय टीम के साथ बात की है। हमारे ढिल्लो साहब और योगेन्द्र मकवाणा साहब भी आए और उन्होंने चर्चा की है कि इस परिस्थिति से लोगों को कैसे उभारा जा सकता है। मान्यवर, इतना ही नहीं विश्व बैंक के अध्यक्ष ने भी वहां आकर रिलीफ वर्क्स को देखा और मुझे गौरव है कि गुजरात की सरकार ने इस तरह के कदम उठाए हैं जिससे कि विश्व बैंक के अध्यक्ष ने भी प्रशंसा की है। मान्यवर, इसके लिए मैं गुजरात की सरकार और गुजरात के लोगों के मनोबल को धन्यवाद देता हूं।

[श्री मीर्जा ईर्शादबेग]

मान्यवर, गुजरात के संबध में मैं कहना चाहूंगा कि आप देखिये वहा कितनी विषम परिस्थिति है और हमारी सहायता कीजिए । गुजरात के 18114 गांवो में से 14829 गांव—17 जिले सूखे से प्रभावित हैं । मान्यवर, 214.74 लाख व्यक्ति इसकी चपेट में है। मान्यवर, 30 जून को 4301 राहत कार्यों मे 10 लाख व्यक्ति मजदूरी कार्य में लगे थे । मान्यवर, जुलाई में, जब यह आशा थी कि वर्षा हो सकती है इस वर्ष जुलाई में 157.75 लाख, अगस्त में 157.47 तथा 5 सितम्बर तक 29 50 लाख मानव दिन राहत कार्य में सलग्न रहे । आज वहां पर 6299 राहत कर्य चल रहे हैं और उसमें 13.47 लाख मजदूर कार्य कर रहे हैं । मान्यवर, आप अनुभव कर सकते है कि वहा इसकी मात्रा कितनी प्रचुर है, वहां इस सूखे से लड़ने के लिए समूचे 2506.09 लाख मानव दिन लगाए हैं । मान्यवर, आज गुजरात को आवश्यकता है 449 करोड रुपयों की आवश्यकता है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हू कि वह हमारी इस कार्य में सहायता करे ।

मान्यवर, अभी यहां पशुओं की बात कही गयी । मान्यवर, यदि एक घर का कुत्ता भी मरता है तो भी दिल में आग लगती है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि आज गुजरात में डेढ़ करोड के करीब एनीमल्स हैं । उनमें से एक करोड़ एनीमल्स इस के प्रभाव में हैं। मैं मांग करता हूं कि समाधन जुटाइए और हमें सहायता दीजिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : इसमें भेड़ बकरी शामिल नही हैं ।

श्री शंकर सिंह वाघेला : वे तो अलग है क्योंकि उनकी सख्या तो जानी भी नहीं जा सकती है।

श्री मीर्जा इर्शादबेग : भेड, बकरी की तो कोई गिनती ही नही है। मैं आपकी बात से सहमत हूं और आपका सहयोग चाहता हूं। मान्यवर गुजरात सरकार आज इस कार्य के लिए प्रतिदिन 1 5 लाख रुपया राहत-कार्यों पर खर्च कर रही है। इन पशुओं के लिए भी रोजाना 60 लाख रुपया कम-से-कम खर्च हो रहा है। मान्यवर वहा 600 से भी ज्यादा कैटल कैम्प लगे हैं। मान्यवर मैं मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि हमारे यहां राहत कार्यों पर जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनके लिए काम के बदले अनाज की एक स्कीम रखी थी और उसमें उनको गेहूं देते थे, तो उसमें गुजरात के लिए एक लाख टन गेहूं केन्द्र सरकार तत्काल रवाना करे। उसके लिए जो उन्होने मापदण्ड रखे हैं, मैं यह माग करूंगा कि 1500 रु प्रति टन से उसको दें और केन्द्र सरकार उसे एम्पलायमेंट जनरेसन स्कीम के अतर्गत शामिल न करें। इसके लिए उसे अलग से दे और राज्य सरकार की जो 7.5 मीट्रिक टन की जो समूची मांग है, उसके लिए मैं चाहूंगा कि मंत्री जी तत्काल

4 00 P.M

अनुमति दें। मान्यवार, पशु आहार की बात है, उसके लिए घास परिवहन के लिए सरकार ने कुछ कानून बनाया और उस पर कुछ सबसिडी दी जाती है। केन्द्र सरकार ने भी राज्य सरकारो को ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज के लिए रिइंबर्समेंट देने की व्यवस्था की है। उसके लिए केन्द्र ने कहा है कि दूसरे इलाको से अगर घास लाई जाती है तो ट्रासपोर्टेशन के लिए 79 प्रतिशत राशि रिइंबर्स की जाती है। अगर राज्य के अन्दर का परिवहन होता है तो 90 प्रतशत दी जाती है । मैं मांग करूंगा कि हमारे राज्य ने इसके लिए जो मांग की है, उसको समूचा सौ प्रतिशत केन्द्र सरकार को ट्रासपोर्टेशन चार्जेज देने चाहिए। मैं मांग करता हूं कि त्वरित गति से इसको वे निपटाए।

श्री गुलाम रसूल मट्टू (जम्मू और काश्मीर) क्या पशु कोई मरा है वहा? . . . **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : He is giving a full picture of what is happening in Gujarat.

श्री मीर्जा इर्शादबेग मान्यवर, प्रधान मंत्री जब वहा पर आए तो उनके सामने विकट परिस्थिति का बयान किया गया, तो उन्होंने कहा कि पंजाब में कुछ मात्रा में है तो वहा से मंगवाया जाएगा। उसके लिए थोडी बहुत राहत मिली भी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि रेल मंत्रालय में उसमें ढिलाई होती है क्योंकि रेल से उसकी ढुलाई होती है। तो मैं चाहूंगा कि रेलवे उस पर कंसेशनल रेट लेकर उसकी

[श्री मीर्जा इर्शाद बेग]

ढुलाई करें। इसके लिए पंजाब में जो स्टेशन नोटिफाइ होने चाहिए थे उनको नोटिफाई करना चाहिए। इसलिए रेल मंत्रालय से मैं मांग करूंगा कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव असर देकर इसकी ढुलाई करवाने की कोशिश करें।

मान्यवर, गुजरात में खरीफ क्राप भी प्रभावित हुई है। आयलसीड्स में देश को अधिक मात्रा में तेल गुजरात से मिलता था। उसकी हालत आज क्या हो गई है कि ऑयल सीड्स 16 25 लाख टन जहां था वहां आज 1.26 लाख टन हुआ। अनाज जहां 31.55 लाख टन होता था आज 2 44 लाख टन हुआ है। कपास जिसके लिए गुजरात नोन था, इसको मैनचेस्टर भी कहा गया है, उसकी परिस्थिति यह है कि इस वर्ष केवल 2.26 लाख टन होने की संभावना है। यह हालत है आज गुजरात के किसानों की।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : मूंगफली के बारे में मुझे फिगर ठीक नहीं लग रही है, इसको आप चैक कर लीजिए ..(**व्यवधान**)

श्री मीर्जा इर्शादबेग इट इज ट्रू। सत्य है। बारिश हुई ही नहीं है वहां। कुओं को गहरा करने के लिए राज्य सरकार ने मांग की है कि कुछ डाइमंड रिग्ज उनको दिए जाएं जिनसे कि पेय जल उनको उपलब्ध हो सके। कुछ सहायता केन्द्र ने दी है। लेकिन अभी उनको डाइमंड रिग्ज उपलब्ध कराए जिसके लिए गुजरात सरकार ने मांग की है।

महोदय, किसानों को रवी सीजन के लिए भी सहायता देना आवश्यक है। इसलिए मैं मांग करूंगा कि उनको पर्याप्त मात्रा में बीज और खाद उपलब्ध कराई जाए। सितंबर 1985 से 533 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं सूखा कार्यों पर और केन्द्र का जो मार्जिन मनी है, उसकी सहायता सहित आज तक 184 करोड़ रुपये ही सरकार को प्राप्त हुए हैं।

This has led to a substantial gap in the resources for the Plan

तो मैं मांग करूंगा कि इसके लिए तुरन्त आप राज्य सरकार की सहायता करें।

मान्यवर, सूखा राहत की केन्द्रीय सहायता के नाम पर जो नियम बने हुए हैं उनमें आज सुधार करने की अत्यंत आवश्यकता है। उसको सरल करने की मैं मांग करता हूं। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा कि गावों में इम्प्लायमेंट जनरेशन के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए 1-4-87 से 30-6-87 तक 20 43 करोड़ रुपया असेस किया गया है। जब कि इस समयावधि में 10062 राहत कार्यों में 13 21 लाख मजदूर काम करते थे और खर्चा इस पर हुआ 41.35 करोड़ रुपये। मैं यह कहना चाहता हूं कि **the expenditure** on employment on relief works should be accepted as per the actuals for the purpose of Central assistance.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Mr. Minister, he is making a very important point.

SHRI MIRZA IRSHADBAIG Sir, he might have noted down my point. Sir, my second suggestion is that the expenditure on non-wage components may vary from 30 to 40 per cent on different kinds of works. Such additional expenditure must be included in the ceiling of expenditure for drought relief otherwise most of the relief work will totally deteriorate and become useless.

एक ओर इम्पोर्टेन्ट बात कहना चाहता हूं और यह बात एइथ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में है।

Sir, the Eighth Finance Commission has accepted that additional staff, specifically recruited for the purpose of relief operations should be treated as a legitimate charge on relief expenditure. The State Government invariably puts the existing administrative machinery to maximum possible use for implementing the relief operations Yet, certain substantially enlarged activities like a large number of relief works, transport and distribution of fodder, transport of water by tankers, etc. require some additional staff in order to ensure proper implementation and supervision The expenditure on such additional staff was not included by the Central Government while approving the ceiling of expenditure...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : You have given so many suggestions.

SHRI MIRZA IRSHADBAIG: Sir, I will make to more points only. Sir, for illustration, I would like to say that an expenditure of Rs. 3.75 crores was incurred on salaries of additional staff specifically employed for relief operations and tools and equipment for relief works during the period from 1-4-1987 to 30-6-1987. This was about 4 per cent of the total relief expenditure—that is about Rs. 98.02 crores—during the same period. Sir, the expenditure on the additional staff was thus at a very low level. It is suggested that a provision at the rate of 5 per cent of the total relief expenditure or 10 per cent of the expenditure on relief works should always be made for additional staff and tools and equipment.

Sir, my next point is that the aged, handicapped, infirm, destitute adults and children who do not have sufficient physical stamina for employment on relief works have to be provided gratuitous relief. The Central Government has fixed the rates of Rs. 2 per adult per day and Re. 1 per child per day. These amounts are too low. That is why, Sir, the State Government is providing this gratuitous relief at the rate of Rs. 4 per adult per day and Rs. 2 per child per day, limited to the ceiling of Rs. 450 per month per family. Sir, the norms followed by the State Government should be accepted for the purpose of calculating the ceiling of expenditure. Sir, I am coming to my last point. I think I am making only one or two points more. The existing policy of the Central assistance for the expenditure on drought relief envisages that subject to the ceiling of the expenditure approved by the Central Government expenditure in excess of 5 per cent of the plan outlay is provided as Central assistance in the form of 50 per cent grant and 50 per cent loan. This policy appears to be all right for an occasional or intermediate drought but when a State faces consecutive droughts, this policy places undue strain on the financial capacity of the State with the result that the progress of some of the normal developmental plans in the State is adversely affected. While the existing policy may be followed for an occasional drought, the pattern of assistance should be changed to 75 per cent grant and 25 per cent loan for second consecutive drought and 100 per cent grant for third and subsequent consecutive droughts.

Sir, the loss of agricultural production from the drought has an adverse effect on the revenues of the State. This reduces the financial capacity of the State Government to finance its normal plan.

Sir, in Gujarat we are facing the third consecutive drought of rare severity. Therefore adjustment of the earlier advance plan assistance should be postponed to better years and 100 per cent Central grant should be given for the expenditure on relief operations against the 1987 drought, particularly because an expenditure of Rs. 98 crores on the drought relief operations has already been incurred up to 30th June, 1987, which is more than the sum of the margin money and 5 per cent of current year's approved plan outlay.

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि जो कानून बने हैं उसके बारे में वाघेला जी ने सच बात कही। गुजरात में यह सब करने के पश्चात् भी वहां पर मवेशियों की मौत हुई है। वहां पर कुछ बकरियां, कुछ शिप्स पर इसका असर पड़ा है और कुछ मरे हैं। कच्छ में क्योंकि इसका प्रभाव सबसे ज्यादा है इसलिये वहां मौतें हुई हैं। लेकिन मान्यवर, आज तक हमारे कानून में इस संबंध में सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं है। मैं मंत्री जी से विनती करूंगा कि मवेशियों और कम से कम छोटे मवेशियों जैसे बकरी आदि इनके सूखे से प्रभावित होने पर उनके लिए सपरेट कानून बनना चाहिए। मैं गुजरात सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने थोड़ा सा इस कानून में कुछ किया है। इसको दूसरे राज्य भी अक्सेप्ट करें तो अच्छा हो। गुजरात सरकार ने इस बात की व्यवस्था की है कि अगर कोई ऐसा पशु बाहर अन्य राज्य में भिजवाना चाहता है तो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देने का प्रावधान किया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि छोटे पशुओं के बारे में कानूनों में सरकार और सुधार करें और उनके लिए ज्यादा सहायता देने की कोशिश करें। मान्यवर, इसके साथ ही अगर कोई स्पेसिफिक कानून नहीं बनता तब तक हम उनको किसी भी हालत में नहीं बचा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि,

[श्री मीर्जा इर्शादबेग]

मकवाना भी लेट से आये, मैंने जो बातें यहां पर कहीं हैं आशा करता हूं कि मंत्री जी ने उनको नोट किया होगा और वे न सिर्फ गुजरात और राजस्थान के संबंध में बल्कि जो भी राज्य सूखे से प्रभावित हैं उनके बारे में मेरे ये सजेशंस अच्छे साबित होंगे। महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये ज्यादा समय दिया इसके लिये मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। जय हिन्द।

श्री शंकर सिंह वाघेला गांव से निकल कर जो गरीब शहरों में आकर झुग्गी-झोंपडी बनाकर रहते हैं ऐसे शहरी गरीबों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। शहर में जो कैटल हैं उनकी गिनती नहीं है मैं चाहता हूं कि उनको भी अकाल के साथ जोडकर उनको भी सुविधा देनी चाहिए ताकि उन्हें भी चारा उपलब्ध हो सके।

श्री भंवर लाल पंवार (राजस्थान) : जब पूरा हाउस इस बात के लिये एक राय है इस वर्ष अकाल से राजस्थान और गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। तो जो बोलने वालों की लिस्ट आपके पास है तो उसमें भी आपको अपना डिसक्रिशन यूज करना चाहिए और इस पर बोलने के लिये प्राथमिकता राजस्थान और गुजरात के मेम्बरों को देनी चाहिए।

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal) : Mr. Vice-Chairman, I do not want to make a speech, at least for relief only. I want to go a little deeper. It has been said by my friend from that side that drought is a natural phenomenon. Therefore, the only response that is called for is when drought descends on us, let there be adequate arrangements for relief. I do not exactly share this perception. Drought today is not as unadulterated natural phenomenon as it was in the past. We know, over the last few years, there are fears expressed all over the world that the climate of our earth is changing, and this is not changing on its own. It is the human greed ; I should qualify that statement; it is the greed of capital which is leading to deforestation, which is leading to hundreds of climatic assults, on the basis of which such droughts would not be an exception to a regular phenomenon on the earth India, as we all know, is considered even by the U.N. agencies as one of the most disaster-prone countries in the world, which means that the greed of apital if it is able to destroy the climatic balance still further, would put us at the losing end. This is not something new which I am suggesting Planning Minister is here. He certainly knows that a hundred years ago, it was said by famous Karl Marx that capitalists in their greed do not not care for nature as they do not care for human lives. They will destroy nature to the disadvantage of the entire society. For this global problem, the only answer can be that let us hasten the process of getting the society rid of capital. That can be the only answer. So long as it persists, so long as the climate would be tampered with recklessly, the human society would be afflicted by this problem and the phenomenon of drought and floods.

Coming to our own country, it is not as if India is only one country; it is many as well. The response or the reaction to drought is not one but there are many responses or reactions. It is not true that everybody suffers in drought There is a section which enjoys drought There is a section which garners further wealth because of drought. And if we look towards the other side of India, India of agricultural labour, India of peasantry, India of middle-classes, and also India of the big landowners and big monopolists, the responses, the suffering and the solutions are not similar. The Government, in a sense, has a reason to be happy. A situation like this permits them to tide over all the differences and the conflicts within the society and appeal for a consensus. I am not one with that approach of the Government Let us see how things have happened and how drought situation developed within our country. This year is not the first year of the drought. On going through the statistics of the number of districts affected we will find that even 1983-84 was affected although that was a year of our record production of foodgrains. Therefore, 1983-84 was also affected. I will give the figures as they are given No. I do not want to go into that. Even then, this year's drought is considered to be a record for the century. When did it start ? In West Bengal, for instance, we have suffered both from drought and floods. Normally, monsoon in West Bengal starts on the 10th of June. But till the

[Shri Nirmal Chatterjee]

middle of July, there was no monsoon. We suffered Now what happens ? If, in the earlier period of the monsoon, there are no rains, who suffers ? It is the agricultural labour of India and nobody else. There is no income for them. They are starving There is no farming on the land. Did the Government react ? The speech is given on the 15th August. The measures are taken later on. Why ? Because those who are suffering are the agricultural labour who have no income. After some time if there is no sowing, after a few days, the peasants begin to suffer. The owner of the land has nothing to offer to the market Simultaneously with this, the urban population, the middle-class, the consumers, who do not have enough, begin to suffer. The consumers, enough, begin to suffer. The responses are always different. When the responses are different, we can immediately find out the reactions of the Government and can understand whose responses the Government is listening to. My query is this . When there were no rains for a full month and a half, why was not the food-for-employment programme stepped up ? You appeal for consensus. Is that enough ? You do not admit the guilt I am, in a certain sense, glad if this drives you away from your disastrous course and complacency. In one single year, the whole glamour of the Green Revolution has been ripped through. Even without drought, for the last three-four consecutive years we were unable to cross the foodgrains production beyond the level of 1983-84. It was criminal negligence on the part of Government of India to have declared India self-sufficient in food, become complacent and not to have done all those things which were promised from the First and Second Five-Year Plan onwards If we can handle human beings better, whatever natural disasters come, we can cope with those disasters also better What is important is your priorities of activity which you lay down There would be fulfilment in Maruti, but failures in irrigation The irrigation projects which were formulated, which were put on paper, and whose execution was said to have commenced in the Second Five-Year Plan, are yet to be completed. You have fulfilled the target of television towers but totally failed with fertilisers. You are not producing enough, yet, there will be a glut and you will not pause to ponder why this has happened because the Green Revolution has taken place Because it is not necessary to enquire whether people are well-fed. It is enough that you are able to stop the import of foodgrains. The targets which are fulfilled are fulfilled for those who are close to the Government. Those targets which relate to the basic masses of our country are forgotten, or only lip service is paid to them. May I make a reference in this connection to the problem of land reforms in the country, to the problem of field channels from the irrigation potential that has been built up, inadequate though it is ? So many obstacles, it seems, have prevented the realisation of the full potential of irrigation, apart from the fact that the targets of irrigation from the Second Five Year Plan onwards have never been fulfilled in our country, unlike that of Marutis It is these things that should make all of us sit up If we really want to tackle the problem of drought at the stage of its inception, we have to ponder whether or not the policies, as formulated and practised, the pattern of our planning itself, need to be drastically revised.

Sir, these are broad questions. You will say, what now ? Firstly, I will say I am unable to talk like our scholarly Minister, Shri P. V Narasimha Rao, who, the other day, said : what bearing has the part on the present ? I do not know what other thing has any bearing on the present or the future. Some other friend will enlighten us if there is anything to go by excepting the past, either superficially or deeply. For the present I will also mention the problem of the State from which I come—West Bengal. Immediately after the drought, the State was overwhelmed with floods And why is there that kind of flooding ? Firstly, the whole conception of DVC, it is said, is ill-conceived because it not comprehensive. But it is not only failure of planning; we know, we will talk about resources. We know that you refuse to collect resources where resources lie. I just make a passing mention that even the financial Ordinance which has been imposed is cynical enough to collect more funds from those who are

[Shri Nirmal Chatterjee]

affected by drought. That is the only, meaning of imposition of more indirect taxes on the common people. But forgiving that, reserving that for another debate, let me make a mention of this that we are at the tail-end of a river. We are at the tail-end of the Indo-Gangetic plain. Our Chief Minister has drawn attention to that Is it not necessary that because of siltages at the sea-bed and lack of ferrying in the Ganges, the suffering would be most at the tail-end of Bihar and South of West Bengal ? Even about the Farakka Project, the Government is repeatedly complaining that the erosion is such that tomorrow the dividing line between Bangladesh and West Bengal may be eliminated by a flood of water At least forgetting that West Bengal is governed by the Left Front Government, and remembering that Bengal is a part of India, is it not necessary that the request for additional flow from West Bengal be acceded to to save a part of India ? The floods in West Bengal would be increasing in intensity year after year because the rivers are not tamed My friend from Gujarat has referred to resources Does he expect that the Government of India will fork out all that amount ? Is it possible to do that ? It is not able to do that also It depends on the States for resources and it is not able to fork out enough to replenish what it has taken from the States.

At least you will concede that the West Bengal Government is much less dishonest than any other State in making estimates at least. They have given a figure of Rs. 450 crores and you dole out some Rs 70 crores Is it an exercise in cynicism ? Or are you dealing in human misery ? They say, nobody has died in drought I don't know about Orissa, but certain deaths have certainly taken place. Look at the child in the drought-affected area; look at his face. You will see that the child is dead. Although he is aged only 12, an adult's face is on his neck The person lives, the child is dead. Is it not death ? This is happening—and what is the response of the Government of India ?

Are the entire people mobilized to fight against flood and drought ? I remember, Sir, the year 1978 as a glorious year in West Bengal. We also said that year, that for 100 years such a flood had not overtaken that State. I remember that year not for that record. I remember that year for the response of the entire people of West Bengal. Its civil staff, its people, its base committees, all the organizations—every single human being—worked hard. The political leaders were certainly at the front. For weeks we did not hear of many of our political leaders. They were deep in the interior in the midst of people at waist-deep water.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Professor, please conclude.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE : I have a meeting at five o'clock. As you know, you are also coming there.

So, I remember this with pride. Can you tell us that the Government of India has succeeded in mobilizing the entire people in that manner ? Can you say that there is such effort instead of depending on bureaucracy to rouse the people to fight this drought ? Can you say this about the ruling parties in the different States ? Cynical statements are made that cattle are dying because of illness and not because of drought, from the same State from which such an eloquent speech was made just before me. And you are not ashamed either, to refuse to recognize the fact and, therefore, to combat it, to mobilize people for that.

I say, Sir, piecemeal demands I don't want to place before you. Our Chief Minister has done it in many forums. I appeal to the conscience of anybody who takes pride of his conscience. To those who have sold it out or to those who have sent it underground, I make no sense But again I request them all to ponder If they want to make a human being out of an agricultural labourer, if they want to make a child grow into a full-blooded adult if they want to see that their women are not sold in th market, please listen to this voice—that your entire Plan priorities have to change. Please remember that even when I heard the talk of difficulties of resources at the Centre, I talk of it only in terms of priorities at the Centre If you

[Shri Nirmal Chatterjee]

change the priorities at the Centre, you will succeed in providing more to the States. I am not here to ask more for West Bengal only. You give more to Rajasthan You give more to Gujarat. I would welcome that But give it to all the States. *Give it to Orissa where, even* without drought, people die of starvation In order to do that, you have to change your policies You have to depend on the people. You have to introduce land reforms. You have to cut back on certain types of expenditure and investment, and instead give priority to the problems of these sections.

Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Before I call Mr. Kulkarni, have I the permission of the House to ask Mr. Chimanbhai Mehta to preside ?

SOME HON. MEMBERS : Yes, yes.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you. Are you changing guard ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : I am sitting there to listen to you.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra) : O.K It does not matter.

[**The Vice-Chairman (Shri Chimanbhai Mehta)** in the Chair]

I think the previous Vice-Chairman who was presiding and also the new Vice-Chairman who is now presiding, for giving me an opportunity to place my views before this august House, and through this august House before the Government, about the conditions of drought, particularly in my State as well as in various other States.

Sir, my young friend from Gujarat made a very nice speech, giving in detail and going into micro-analysis what is needed and what is not needed But, Sir, I have got a different approach towards the drought problems

I would think that the Ministry would not misunderstand me if I bring to their notice the difficulties of the various States in meeting the obligations and meeting the State Plan priorities If you go through the replies to various questions, you will find this I will refer only to the questions and the Government replies particularly about drought assistance to various States.

Sir, very recently a question came up on 12-11-87, which I had asked in connection with the assistance that had been provided to various States. Sir, in 1986-87 the assistance required was Rs. 4,762 crores, and the approved ceiling for that year was Rs. 609 crores. That means a niggardly amount of 8 to 10 per cent Then, Sir, again in 1987-88, taking the overlapping of *both the years, the total* requirement was about Rs. 7,800 crores, but the assistance provided was about Rs. 1,046 crores. It means roughly 10 to 12 per cent.

Sir. I am bringing in this point, through you, for the consideration of the Government. Such a niggardly assistance creates problems. Either the State Governments must be over ambitious in placing their requirement or the Central Government must be allotting certain norms which are either not realistic or, if they are realistic, are totally irrelevant to the problem which is going to be faced by the country. They do not meet the aspirations of the States. Since they do not meet the aspirations of the States, the States will not be able to meet the aspirations of the affected persons, and, thereby, the entire plan priorities of the States will be distorted. I just referred to the 7th Finance Commission Where were the norms given ? Now, 8th Finance Commission is applying its mind. In the meantime the Ministry must have raised those norms I do agree that the Ministry must have raised those norms, but these norms, as I pointed out to you, *fall too short of expectations Even tak*ing for granted that 30 per cent demand of the States is bogus or uncalled for, the ratio of the sanction or of the approval by the Central Government rises from ten to fourteen per cent. States are not beggers. They are the assets of this country. And if you weaken the States, you will weaken yourself

SHRI SHANKER SINH VAGHELA : But the Central Government is treating the States as beggars.

SHRI A G. KULKARNI: I am a little bit old and cannot listen that.

That is why my first point is on this ground. The hon. Minister and the Minister of State both are sitting here and perhaps they have understood this difficulty. The Central Government, the Minister of Agriculture and even the Prime Minister himself have stated that there will be no shortage of drinking water The Maharashtra Government's requirement for drinking water has come from different plan heads. If you look at the different plan heads for drinking water supply in rural and urban areas for 1986-87, the amount spent on emergency measures for it and the plan and non-plan expenditure in 1987-88, you will find that in 1986-87 alone drinking water requirement of the Maharashtra State was Rs. 205 crores and its fooder requirement was Rs 30 crores. But the total requirement of the Maharashtra Government on total drought effort, plan and non-plan, emergency and various other schemes was about Rs. 495 crores or Rs. 500 crores What was the total amount sanctioned? It was only Rs. 97 crores. And the requirement on drinking water and all that for 1986-87 was Rs. 205 crores. For fodder it was Rs 30 crores In such a situation how can you expect that the people will get drinking water? How do you expect that the cattle will survive? This is for 1986-87. During 1987-88 the Maharashtra Government made a demand of Rs 194 23 crores for drinking water I am only talking of the drinking water problem now. Leave aside other problems. Against a demand of Rs 143 23 crores only Rs 37 crores was sanctioned. Out of that Rs 25 crores is overlapping with 1986-87. Only Rs. 12 crores is the sanctioned amount plus Rs. 18 crores sanctioned very recently.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): For your information we add MNP and Accelerated. Rural Water Supply Programme You add it also This is only drought relief.

SHRI A. G. KULKARNI: But how will those programmes even keep going when the erosion of the plan funds has come up to 50 per cent? How do you expect the NREP, IRDP and others to take place at all? Mr. Makwana, I do not want to pick up a quarrel on that because I want to adopt the line of Birlaji, just to beg. What is the use of criticising Mr. Makwana, in my own district four villages in drought affected areas have stopped the employment Guarantee Scheme Now because of the late rains drinking water is available But only God will have to help the people from March/April to June/July when the rains are expected after this period But leave aside this point but the niggardly assistance to the States has got a danger. You are not only giving them 10 per cent of the demand but also distorting their plan priorities What you are talking of is IRDP, NREP and RLEGP.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I mentioned about A.R W S P.

SHRI A. G KULKARNI Whatever it is, they will also be affected because of the total resources shortage and total resources crunch of the State Government.

Then, Sir, another point

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : महोदय, 29 करोड रुपया रूरल ड्रिंकिग वाटर और मीनिमम नीड्स प्रोग्राम के अंतर्गत आपकी गवर्नमेंट के पास पडा हुआ है 11-11-87 तक जो अनयूटिलाइज्ड है ।

SHRI A G. KULKARNI: You say "what you have given to the Maharashtra Government was unspent." I said total demand is Rs. 205 crores. This has been given to me and I have also estimated. Out of that you have only sanctioned Rs. 97 crores for 1986-87.

कृषि मंत्री (श्री जी. एस. ढिल्लो) महाराष्ट्र का बजट थोड़ा देखें तो थोडा . . . . .

SHRI A. G KULKARNI: Mr Minister I am not asking for the whole Maharashtra Government's budget If the money has not been spent it does not mean that the Maharashtra Government does not need money. The point is there is a process of money spending and that process has to go You are talking as if you are

[Shri A. G Kulkarni]
giving the money out of your pocket. Sir, the second point is......

श्री रामानन्द यादव : कच्छ में टेक्नोलोजी मिशन के अंतर्गत 2 करोड 90 लाख रुपया दिया है, जो अभी तक खर्च नही किया गया है।

श्री शंकर सिंह वाघेला · खर्च नही करती है वह सरकार तो उसको खीचिए।

श्री रामानन्द यादव आपको भी मैंने खत लिखा कि आप कच्छ मे आइए, लेकिन आप नही आए।

I wrote a letter before I visited your sate I have visited your State thrice and you were not present and I have mentioned in my leter that we will discuss about drought problem and drinking water supply problem

श्री शंकर सिंह वाघेला : राज्यो के झगड़े मे लोग मारे जा रहे हैं।

we have requested for an appointment with the Prime Minister on the basis of our representation but nobody is giving us appointment

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI CHIMANBHAI MEHTA) : If the Minister interrupts like this, then, I will allow the Member also to answer.

SHRI A. G. KULKARNI : What the Minister is talking is about technology and other programmes. These are all programmes embodied in the State's plan. The drought plan is a separate plan. When there is no money in the total kitty what is the use of saying that Rs. 25 crores has not been spent by the State Government? The State Government is spending money on its own.

Regarding Gujarat what you have said just now is contrary to what my hon. friend, Mr Mirza, has said He has given a certificate to the Gujarat Chief Minister. I think either you do not know what you are talking or my hon. friend, Mr. Mirza might not be knowing what he spoke.

श्री रामानन्द यादव · आपको कुछ पता नहीं है। **(व्यवधान)**

SHRI A. G KULKARNI I can understand your knowledge about Bihar but not of Maharashtra and Gujarat आपको बिहार का मालूम ही होगा, महाराष्ट्र का नही।

SHRI RAMANAND YADAV : Till now what you have done I have a record from all the State Governments.

SHRI A G KULKARNI : The papers which are fluttering might have been given by your officers who would have obtained them from the Tahsildars. But we have collected figures from our own experience.

श्री रामानन्द यादव हमारे माननीय सदस्य को मालूम है कि मैं तीन दफे आपकी स्टेट मे भ्रमण कर चुका हूं। आपको भी पत्र मिला होगा जो मैंने लिखा था, आप भी नही आए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI CHIMANBHAI MEHTA) : Please allow the Member to proceed.

SHRI A G. KULKARNI : The system is such and the refund procedure is such that the Central Government is yet to pay back to the Maharashtra Government I am talking about plan erosion because of drought and non receipt of funds. Sir, the electricity duty which was discussed here has not been refunded till today. Maharashtra State is receiving less money than what they have spent there. I would ask Mr Ramanand Yadav and the Senior Minister also, there is a reply of 13th November—long term scheme to prevent occurrence of drought.

आप * करते है। आपका जो यह कागज है पहले यह पढ़ लीजिए। आप हिन्दी समझते हैं इसलिए हिन्दी मे बोल रहा हूं।

Out of that, what have you done and this is the fourth year when Maharashtra State is facing drought? If you had done 1/10th of the norms or the guidelines which you have printed here, the State Government and the various States would have been saved from the drought.

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) : *शब्द को अमेंड करवा दीजिए।

श्री जी. एस. ढिल्लों : यह * क्यों कहते है?

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : ठीक है मैं इररिलेवेंट बात कह देता हूं।

*Expunged as ordered by the Chairman

[श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी]

Now, you have studied all these things. रामानन्द जी बोलते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। वह बोलते हैं तो हम सुन लेते हैं।

Sir, what I want to say is that if these are the guidelines, then this is the fourth year that the drought has come not only in the State of Maharashtra but Rajasthan, Gujarat and there are many other States Sir, I do think even taking for granted here they say, the research is being done to get the dwarf varieties of oil-seeds, proteins etc. Here is Sir another certificate dated 12th November from Dr. Randhawa who is the Secretary of the Minister of Agriculture and Director of Indian Council of Agricultural Research, and what he says is that he deplored that not a single institution in the country is providing meaningful research when the nation was badly in need of it, something which would bring about more yield in a given agro-climatic conditions is not coming up and he appealed to the 23,000 agricultural scientists to apply their minds. He criticised like that So about the guidelines I do feel and the Minister should take it very seriously that the research programmes in agriculture are lacking. That is why, we are facing more drought, more difficulties and less foodgrains on that account. I do feel the research in oil-seeds and pulses is not only lacking but is not giving any results.

Sir, about the last two points which I am making I think, Sir. the approved ceiling of the Maharashtra State is too meagre. Out of that Rs. 25 crores what Mr. Ramanand Yadav says and I will immediately find out from the State Government as to what are the facts, he says that Rs 25 crores have been given to Maharashtra apart from these approvals. They are separate from this or they are included in this. क्या है भई ? आप डर गए न ?

श्री रामानन्द यादव : मैं डरा नहीं हूं। अभी आपके पास बहुत पैसा बाकी है।

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : पैसा जो 25 करोड़ का पडा है यह एक पैसे के माफिक भी नहीं है।

The money required is about Rs. 800 crores. So, Sir I come to my point.

श्री आ. एस. विल्सों यह झगड़ा बन्द कर दीजिए। जब मैं जवाब दूंगा उस वक्त सब साफ कर दूंगा। यह आपस की दोस्ती में ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो अनपार्लियामेंटर हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI CHIMANBHAI MEHTA) . That will be taken care of Whatever is unparliamentary may be taken off

SHRI A. G. KULKARNI . I have no disrespect for my friend, Mr. Ramanand Yadav. Nothing unparliamentary will go on record But the basic facts are there and they should remain on the record for the Government's information I told you about fodder I have also quoted how much money was required and how much was granted Sir, in Maharashtra, at Dhulia in Thane District—I have read and I have not gone there—an Adivasi area, certain deaths due to malnutrition and shortage of food have occurred It will be better for the Government to enquire of the State Government as to what the facts are on this. I will require that.

Sir, I would require a specific reply as to what money you have sanctioned. It has come as a parliamentary reply, and not 'between you and me', just like a discussion, to a question dated 12th November, 1987 It says about the total funds sanctioned to various States Whereas Rs. 553 crores is the demand, inclusive of various programmes, the amount sanctioned is Rs 97 24 crores for 1986-87 The amount demanded is Rs. 294 crores for 1987-88 whereas the amount released is Rs 37.67 crores. Out of that Rs. 25 crores was overlapping and Rs. 12 crores new. Will the Minister clarify what the figures comprised? What are the demands made against each item and which items did they accept and which items did they feel superfluous or unjustified claims?

The next point is : Is there any possibility that in the case of States which are facing drought for the last three or four years, the norms can be changed in respect of creation of funds? The Central Government is empowered to create funds, to collect funds, either by various loans or by various other means The Central Government has got financial instruments The State Governments have only limited instruments When the Finance Commission

[Shri A. G Kulkarni]

will go into this is a different matter. The utmost necessity at present for the Central Government is to empower the States to create funds or to provide the funds themselves and see that their plan priorities are not eroded At present what I see is that plan priorities are eroded and it cannot be like this.

The last point which I want to make is, as I understand from Mr. Makwana, it seems a view has been taken by the Central Government that the Maharashtra Government is not facing a severe drought From where did you get this information? What we have got is information from the State Government. I do not know where you got that information from. I do feel that Maharashtra is equally affected and it will be better for the Central Government to find out reasources so that the Maharashtra Government can meet the challenge properly. Thank you.

5.00 P.M.

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : महोदय, क्योंकि मैं जाना चाहता था इसलिए आपने मुझे अनुमति दी । धन्यवाद ।

जिस मसले पर हम विचार कर रहे हैं, सुखाड़ और बाढ़ के, हमारे हिसाब से सरकार इन बातों को सही ढग से समझ नहीं रही है। इस बाढ़ और सुखाड के चलते पिछली दो-तीन योजनाओं में जितने लोगो को हमने बिलो-पावर्टी लाइन से ऊपर किया था उससे ज्यादा लोग बिलो पावर्टी लाइन चले गये हैं। पिछली दो-तीन योजनाओं में जितने मकान हमने बनवाये थे उससे दुगने मकान इस बाढ में ढह कर खत्म हो गये हैं । जितने मवेशियों को आपने ऊंची नस्ल दे कर अच्छा किया था उससे कई गुना ज्यादा मवेशी मर गये हैं उनका खात्मा हो गया है । इसलिए इस बार की बाढ़ और सुखाड़ ने एक बडी समस्या पैदा कर दी है कि नये ढग से हम लोगों को अपनी प्लानिग के बारे में सोचना चाहिये । अगर सरकार ऐसा नही करती है तो इस बार तो आपके पास अन्न का स्टाक था इसीलिए बहुत से लोगों को बचाने में आप कामयाब भी हुए हैं, वैसे बहुत से लोग मरे भी हैं लेकिन अगर यह सुखाड़ एक बार और हो जाए जैसे कि अभी पिछले वर्षों में दो बार जल्दी-जल्दी हुआ है तो मुझे इस बात की भयकर आशका है कि हमारा देश उन देशों में से हो जाएगा जो दक्षिण अफ्रीका के देश हैं और जो कर्ज में डूबे हुए हैं । हमारा देश अभी भी ब्राजील, मैक्सिको, साउथ कोरिया, इन्डोनेशिया और अर्जनटाइना के बाद भारत ही विश्व में ऐसा देश है जिस पर सब से ज्यादा विदेशी कर्ज है । अभी वर्ल्ड बैंक या दूसरे स्रोत से कर्ज सस्ता मिलना बंद हो गया है। अब हम मार्किट लोन के लिए जा रहे हैं। इसीलिए हमको खतरा है अगर सरकार ने हम लोगों की इस बात को नही सुना प्लानिंग का रिओरियेंटेशन नही किया गया तो हमारा भविष्य बहुत ही अन्धकारपूर्ण होने जा रहा है। अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने अकाल के लिए बहुत अच्छा काम किया है । इस सिलसिले में हम आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे हिन्दुस्तान टाइम्स समाचार पत्र में तीन तारीख को एक यह समाचार छपा है कि एक आदिवासी महिला ने भूखे बच्चों को छोड दिया और भेड़िया उसको खा गया । मैं मत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उनको यह समाचार मिला है या नही मिला है। अगर यह समाचार उनको मिला है तो उन्होंने इस पर क्या कार्यवाही की है? सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि मवेशी नही मरे हैं। मैं एक उदाहरण इण्डियन एक्सप्रेस का दे रहा हूं जिसको मैं आपके सामने कोट करता हूं,

"Of the 5 8 lakhs, sixty thousand have died of hunger and thirst and another ninety thousand are on the verge of collapse "

इसी अखबार का कहना है कि कच्छ क्षेत्र में 50% मवेशी समाप्त हो जाएगे । मैं मत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि क्या यह जो सारी बातें अखबार में छपी हैं यह बातें गलत आ रही हैं, क्या आपने इसके बारे में कोई खण्डन किया है या आपने कोई जाच करवाई है, अगर जाच करवाई है तो आप उसे सदन के सामने प्रस्तुत करें । जहां तक हमारे बिहार का ताल्लुक है हमारे यहा इस बार की बाढ़ के चलते सब से ज्यादा बरबादी हुई है । सारे देश में जितनी बाढ़ आती है उसका वन फिफ्थ बिहार में आता है । यह प्रकृति की देन नहीं है । यह कांग्रेस सरकार की देन है । यह मैं सब से पहली बात आपसे कहना चाहूंगा । क्योंकि हमारे यहां

[श्री चतुरानन मिश्र]

जो बाढ़ आती है मुख्यतया कोसी, कमला और बाघमती ग्रुप की नदियों से जो नेपाल से यहां नदियां आती हैं उनमें आती है। नेपाल सरकार ने स्वीकार किया था अगर कोसी के बराह क्षेत्र में और कमला के शीशापानी में बाघमती के नूमथर इलाके में डैम बनाया जाए तो इन सारी नदियों में बाढ़ नहीं आती और इससे बिहार बच सकता था लेकिन हमारी सरकार ने कहा कि अगर बराह क्षेत्र में यह योजना बनेगी मल्टी-परपज डैम बना तो इतनी बिजली पैदा होगी इतना पानी मिलेगा कि हम बिजली खर्च कहां करेंगे। मैं भारत सरकार के एडीशनल सैक्रेटरी के लैटर से एक उद्धरण आपको सुना देता हूं।

"There is no market for power and sored water not required for irrigation."

यह नेपाल की सरकार नहीं कहती है यह भारत सरकार कहती है कि इतना पानी और इतनी बिजली लेकर हम क्या करेंगे। इसी के चलते इन तीनों जगहों पर डैम नहीं बना और नतीजा यह होता है कि हर साल बाढ़ आती है। मैं यहां यह भी बता दूं कि एक अपडेटेड फीजिबिलिटी रिपोर्ट नेपाल सरकार को भारत सरकार द्वारा भेजी गई जिसके अनुसार 3000 मैगावाट बिजली का उत्पादन होता था आज बिजली का संकट भी नहीं होता और यह बाढ़ भी नहीं होती और बिहार के लोग भी बच जाते। बिहार ही नहीं मैं आपसे कहूंगा कि गंगा में तब उतना पानी नहीं आता, गंगा भी फ्लडेड नहीं होती और पटना तथा जहानाबाद बच जाते। और तब फरक्का के लिए जो पानी के लिए इतना कोलाहल करते रहे हैं वह कलकत्ता पोर्ट भी बच सकता था। गंगा को कावेरी ले जाने की बात आपने सुनी होगी। सरकार इन कामों को नहीं करती है। नतीजा यह हुआ है कि इस बार हमारे जितने इम्बैंकमेंट थे बिहार के उन सभी की लाइफ एक्सपायर हो गयी है। इम्बैंकमेंट्स अब समतल जमीन से 7 या 8 फीट ऊपर हैं। इस साल इस बाढ़ का पानी 7-8 फीट ऊपर से बहा है अर्थात् रिवर का बेड जो है वही ऊंचा हो गया और धरती नीचे हो गयी है। इसीलिए रिपेयरिंग से इसका काम नहीं चलेगा और बिहार को सर्वनाश की ओर ले जाने का एक मुख्य कारण यही है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करें, नहीं तो एक और खतरनाक बात होगी लोगों को रीजनलिज्म की तरफ ले जाने की . . . (**समय की घंटी**) दो मिनट का समय और ले लेता हूं।

आखिर में कन्क्लूड कर देता हूं। आप इन बातों को नहीं सुनते हैं जो मरते हैं उनकी बात नहीं सुनते हैं। अभी बड़े पैमाने पर लोग बिहार में गृह विहीन होकर पड़े हुए हैं। उनके खेत सूने हैं उनको खाने के लिए नहीं है। सरकार कुछ ठोस कर नहीं रही है। ऐसी हालत में आंदोलन उठेगा जो सेपरेटिज्म की तरफ जायेगा तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आप पर होगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बिहार की समस्या पर, बाढ़ और सूखे की समस्या पर गम्भीरता से विचार करें, पूरी प्लानिंग का रीओरियंटेशन करें नहीं तो सारा देश रसातल में चला जायेगा। यही मैं आपसे अनुरोध कर रहा था। इन बातों पर सरकार गम्भीरता से विचार करे। आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्रीमती प्रतिभा सिंह (बिहार) श्रीमन, आज बाढ़ और सूखा पर बहस हो रही है। सूखा पर काफी सदस्य बोल चुके हैं जिस प्रदेश, बिहार से मैं आती हूं वह प्रदेश, बंगाल, अरुणाचल, उत्तर प्रदेश या सारे इस तरफ के जो भी प्रदेश हैं उनमें बाढ़ की जो विभीषिका है वह इस साल बहुत अधिक रही है। इसके दो कारण हैं। मुझसे पहले भी माननीय सदस्यों ने इस पर चर्चा की है और बताने की कोशिश की है कि एक तो वर्षा कुछ अधिक हुई है और दूसरा पहाड़ों में पेड़ कट गये हैं। इसलिए पहले जो नदियों का पानी आता था थोड़ा रुक-रुक कर आता था, अब सीधे पहुंचता है और उनका जोर और दवाव बहुत अधिक होता है। जैसा मैंने कहा कि मैं सुखाड़ पर इतनी चर्चा नहीं करना चाहती हूं। मैं अपनी बातें बाढ़ पर ही रखना चाहती हूं और वह भी विशेषकर बिहार की परिस्थिति पर।

बिहार में, विशेषकर उत्तर बिहार के जिले—जैसे चम्पारन, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा आदि हैं ये विशेष क्षतिग्रस्त हैं। उदाहरण के लिए मैं केवल एक ही जिले सीतामढ़ी की बात कहूं। इस जिले की करीब एक करोड़ से अधिक की सम्पत्ति की क्षति हुई

[श्रीमती प्रतिभा सिंह]

है। पूरे बिहार में 10287·38 लाख की सम्पत्ति को क्षति हुई है। 23·1 लाख हेक्टेयर क्षतिग्रस्त है जहां से फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। सुरक्षा प्राप्त परिवारों की संख्या 84404 लाख के करीब है। 84 ब्लाक बाढ़ से पीड़ित हैं जिसमें केवल सीतामढ़ी में 16 ब्लाक हैं। वैसे सब आकड़े मेरे पास हैं लेकिन मैं उन आकड़ों में न जाकर दूसरी बातें जो सरकार के सामने रखना

[उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) पीठासीन हुए] ..

चाहती हूं उनमें ही जाऊंगी। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोपालगंज, सिवान, सारन, वैशाली, मोतिहारी इन सभी स्थानों में आज कोई रोड नहीं है। बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में, नेपाल से जो नदियां आती हैं, कुछ बड़ी नदियां हैं और कुछ छोटी भी नदियां हैं इन सबमें बहुत जोर से पानी आता है और जो कुछ उसके सामने आता है उन सबको तोड़फोड़ देता है। फसल में धान, मक्का, तिलहन, दलहन, जो कुछ भी था, सब बाढ़ के मारे नष्ट हो गया है। परिवारों के सहायता कार्य में बिहार में 155 करोड़ रुपये सहायतार्थ खर्च किया है, हर तरह से परिवारों को पशुधन आदि को सुरक्षित करने की सरकार ने चेष्टा की है। फिर भी बहुत क्षति हुई है।

इतनी बड़ी क्षति को देखते हुए केन्द्रीय सरकार से 55 करोड़ का जो अनुदान मिला है, मेरे ख्याल से यह ऊंट के मुंह में जीरे का फोरन है क्योंकि इतनी बड़ी क्षति हुई है कि बिहार सरकार 155 करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है। तो उसमें 55 करोड़ सिर्फ एक-तिहाई ही होता है।

अभी दो-चार दिन पहले ही मान्यवर कृषि मंत्री मकवाणा जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 244·16 करोड़ रुपया दस सूबों में आवंटित होगा। जो यहां पर परिस्थिति बताई गई, हर सूबे की परिस्थिति चाहे वहां बाढ़ या सुखाड़ है, हरेक की परिस्थिति इतनी दयनीय और गम्भीर हो गई है कि उसके लिए मेरे हिसाब से यह राशि बहुत कम है और मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करूंगी कि अलग-अलग विभागों

इस बार बिहार में एक बार नहीं, तीन-तीन बार बाढ़ का प्रकोप आया है। कुछ लोगों ने फिर कुछ जमाने की कोशिश की, बीज लाए, लेकिन फिर से नष्ट हो गया। तो इसलिए मैं कुछ बातों पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं जैसे राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड, नेशनल फ्लड कंट्रोल बोर्ड 1954 में स्थापित हुआ था और तब से यह कार्य कर रहा है, सारी जगह आकड़े जमा कर रहा है, सब कुछ इसने किया है, लेकिन जो देखने में आता है वह यह है कि हर साल बाढ़ की विभीषिका बढ़ती ही जा रही है, घट नहीं रही है।

इसलिए मेरा निवेदन यह है कि सरकार को इस पर कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत थी कि आखिर कहां पर दिक्कत हो रही है, लूपहोल कहां पर है, क्या परेशानी है जिसकी वजह से उनके सुझावों को हम कार्यान्वित नहीं कर पा रहे हैं? यह तो एक बोर्ड की बात कही क्योंकि बाढ़ से जो क्षतिग्रस्त स्थान हैं, चाहे वह बंगाल, बिहार, असम या उत्तर-प्रदेश हो, जो जगह हैं, वह लोकेटेड हैं, जो नदियां हैं, वह भी लोकेटेड हैं, और जो फैक्टर्स आपरेट करते हैं, वह भी लोकेटेड हैं, फिर क्यों मुश्किल हो रही है? बाढ़ निक्कासी इत्यादी की कल्पना प्रथम पंचवर्षीय योजना से हो चल रही है। तो अभी तक कोई रास्ता हम नहीं खोज पाये कि क्या हो और कैसे हो। क्योंकि आज तक इसका परिणाम लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

नेशनल फ्लड कमीशन एक दूसरा है, इस राष्ट्रीय बाढ़ कमीशन की रिपोर्ट 1976 में सरकार को दे दी गई थी, उसके सुझाव कार्यान्वित हुए या नहीं हुए?

कोसी टैक्नीकल कमेटी 1965 में स्टेट गवर्नमेंट ने बिहार में बनाई। उसने सुझाव दिया कि कोसी पर सेकंड बराज बना दिया जाए। अभी तक कोसी की पूर्वी और पश्चिमी नहर जो है, वह भी पूरी नहीं हुई।

पटना बाढ़ कमेटी, जो 1975 में बहुत भारी बाढ़ आई, उसके बाद उस कमेटी ने सुझाव दिया कि एम्बैकमेंट पर मेसानरी वाल्स बनाई जाये। उनमें क्या प्रगति हुई?

सेंट्रल कमेटीज जो बनी, उसमें फ्लड कंट्रोल अधवाड़ा ग्रुप्स आफ रिवर्ज के लिए

चेनेलाईज किया जाए और पानी का कुछ हिस्सा डाइवर्ट करके कमला में डाल दिया जाए। यह अधवाड़ा के बारे में मेरी विशेष रूचि इसलिए है कि मैं सीतामढ़ी जिला से आती हूं और माननीय मंत्री जी को भी मालूम है कि अंधवाड़ा ग्रुप आफ रिवर्ज उसी एरिया में है और उस एरिया का जो नुकसान होता है, वह मुझ से अधिक मंत्री महोदय जानते हैं।

सेंट्रल कमेटी आफ नार्थ बिहार ड्रेनेज कमेटी 1965 में बनाई गई थी। उसने ड्रेनेज आदि के सुझाव दिये। वह सुझाव कहां गए और उन पर क्या कार्य हुआ ? गंडक हाई लेवल कमेटी 1971 में बनी और उसने स्टोरेज प्लान वगरह का सुझाव दिया। ये सारी बातें कहां पर हैं, कहां पर क्या हो रहा है, यह समझ में नहीं आता है? इसीलिए आज मैं बड़े दुख से कह रही हूं और आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि इन पर विशेष ध्यान दिया जाए। बिहार में शंकरानन्द जी पहले गए थे वे सारे बिहार में बाढ़ की स्थिति को देख आए, दरभंगा में, सीतामढ़ी में, मुजफ्फरपुर और चंपारन में। और राजेश पायलट जी सीतामढ़ी से कुम्मा तक गए। लेकिन आगे नहीं जा सके, तो क्या नहीं जा सके? इसलिए कि सड़क नहीं थी कोई रास्ता नहीं था। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहती हूं कि बाढ़ हर साल आती है, और हर साल हम लोग अपना दुख-दर्द वहां की जनता की परेशानी वहां की सरकार को राशि की कमी होने से उसकी दिक्कत, इन सारी बातों का वर्णन हम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ होना चाहिए वह नहीं होता है। हर साल हमारी तकलीफ और दुख-दर्द बढ़ता जाता है और घटता कभी नहीं है। आज तक फ्लड प्रोटेक्शन मेजर्ज इनएडीक्वेट क्यों हैं? नदियों का वही स्थान है फिर तरीका क्यों नहीं निकला? तटबंध कमजोर क्यों बनते हैं? वे पानी के झटके को बर्दाशत नहीं कर पाते। सड़कें जहां पर काज-वे होना चाहिए वहां पर ओवर ब्रिज बन जाता है और जहां पर ओवर ब्रिज बनना चाहिए वहां पर काज-वे बन जाता है। तो जाहिर है कि न इधर फायदा होता है और न उधर फायदा होता है। जो पैसा खर्च हुआ वह अलग खर्च हुआ और वह साल भर के अन्दर नष्ट हो जाता है। इन बातों के लिए कौन सोचेगा और कब सोचेगा ? नदियों को एक दूसरे से जोड़ करके जरूरत की जगह कैसे पहुंचाया जाए इसका प्रबन्ध और इसके बारे में बहुत सारे सुझाव माननीय सदस्यों ने दिए और कई कमेटीज ने दिए हैं। के. एल. राव के समय मुझे ध्यान है कि कई बातें आई थीं गंगा-कावेरी जोड़ने की और भी कई बातें आई थीं लेकिन कुछ नहीं हुआ। नहरों की ड्रेजिंग का प्रबंध नहीं है और नहरों की खुदाई अधूरी छोड़ दी है। मैंने पहले भी कहा कि बागमती, कोसी, कमला, गंडक, अंदवाड़ा ग्रुप सभी की योजना बनी, यहां तक की लोहा-लकड़ी भी वहां पर फेंक दिए गए, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। घर भी बन गया। अधूरा काम जो हुआ उस पर सरकार का पैसा तो खर्च हुआ ही साथ ही बाढ़ का प्रकोप भी अधिक हुआ। साथ ही चीजों के दाम भी बढ़ गए। जो साढ़े चार सौ करोड़ की योजना थी अब वह हजार सौ करोड की हो गई। जाहिर है कि कहां से पैसे आए और काम कैसे पूरा हो और अब अधूरी योजना की वजह से जो पानी पहले बह जाता था वह रुक जाता है और ज्यादा मवेशियों, खेती, आदमियों सभी का नुकसान हो जाता है। सुख देने की जगह पर इन सभी नदियों ने दुख देना शुरू कर दिया है। कोसी नदी का काम 1958 में आरंभ हुआ किन्तु अभी भी नहर निर्माण चालू है। आज समय है कि इन प्रश्नों पर गंभीरता से हम विचार करें, इन सवालों पर विचार करें कि कितनी राशि बाढ़ और सुखाड़ के समय हम हर साल खर्च करते हैं। कितनी सम्पत्ति, फसल और पशुधन की क्षति हर साल होती है और कितने हैक्टेयर्ज भूमि बेकार पड़ जाती है ?

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : अब आप कन्क्लूड करिए।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : थोड़ा सा और कहकर करती हूं। क्या हम इस क्षति को पूरा कर सकते हैं? यह सब क्यों होता है? एक बार में ही प्लानिंग बना करके यह जो इतनी बड़ी राशि हम खर्च करते हैं क्या उसके आधे में ही बाढ़ नियंत्रण का काम नहीं कर सकते ? सिंचाई की योजना का जब निर्माण होता है तो उसके लिए जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है वे सब कहां से मुहैया होंगी इसकी भी

[श्रीमती प्रतिभा सिंह]
कर टैक्नीकल नो हाउ तथा दूसरे सभी सामान कोल, काटा सभी कुछ कहां से आएगा। समय पर मिलेगा या नहीं, इत्यादि पर विचार होना चाहिए। बिहार में तो बाढ़-नियत्रण तब तक संभव नहीं होगा, जब तक की नेपाल के साथ हमारी पूरी तरह से बातचीत नही होती, समझौता नहीं हो जाता। इसलिए इस पर शीघ्र से शीघ्र विचार होना चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी हाल में दो-चार दिन पहले इस पर सवाल भी उठा था और मेरा ख्याल है कि साठे जी या सुशीला जी ने कुछ जवाब भी दिया था। वर्ल्ड-बैंक की कौन सी योजना है, कौन लोग निर्णय करते हैं, बिहार में बाढ-नियंत्रण के काम में वर्ल्ड बैंक की फाइनेन्स की कैसे व्यवस्था हो, कैसे उपयोग हो क्योंकि अभी तक बिहार में एक भी योजना वर्ल्ड-बैंक ने इस विषय में नहीं ली है। उपसभाध्यक्ष महोदय, बिहार एक तो यों ही पिछड़ा प्रदेश है और इस बार की बाढ ने तो इस प्रदेश के जनजीवन को बिल्कुल ही तहस-नहस कर दिया है। सड़क नाम की चीज उत्तर-बिहार में तो रही नही। अत: मेरा सुझाव है कि नेपाल की सीमा के साथ संलग्न क्षेत्रों में, जिस प्रकार नेपाल सरकार ने पूर्वी और पश्चिमी राजपथ का निर्माण किया है, वैसी ही योजना केन्द्र सरकार सड़को की बनाए। साथ ही सड़कों की रिपेयर के लिए विशेष धनराशि उपलब्ध कराए क्योंकि सड़क सबसे अनावश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर है । उसके बिना तो राहत-सामान भी नहीं पहुंच सकते हैं सुदूर गांवों में। भले हो कागज पर पहुंच जायें, लेकिन गाव में तो नही पहुंचता । मेडिकल-एड वहा लोगो को नहीं मिल पाती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, बैंक घर बनाने के लिए सस्ती दर पर कर्ज दे और खेती के लिए, बीज तथा फर्टिलाइजर उपलब्ध कराए। जो 150 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने खर्च किया है, उतना तो कम से कम केन्द्र सरकार देने का कष्ट करे । बिहार सरकार ने मास्टर प्लान बाढ़-नियंत्रण के लिए 480 करोड़ रुपए का भेजा है, जिसको कार्यान्वित करने से 14.80 लाख हेक्टेयर भूमि पर बाढ का नियंत्रण हो सकेगा। बाद में एक और भी इण्टीग्रेटेड एक्शन प्लान सन 1978 में भेजा गया, जिसका प्लान आउटले 870 करोड़ था और समय इसमें पाच से सात वर्ष सिर्फ लगने हैं, इससे 28.33 लाख हेक्टेयर भूमि पर बाढ़-नियंत्रण हो जाता है . . . . . . (व्यवधान) . . .

श्रीमती प्रतिभा सिंह बस एक मिनिट। कन्क्ल्यूड कीजिए।

श्रीमती प्रतिभा सिंह बस एक मिन्ट । इसके अन्दर पानी स्टोरेज का प्रबंध होगा, तटबंधों की मरम्मत होगी। इस प्रकार से प्रदेश के अंदर फ्लड-कुशन तैयार होंगे।

रेलों की मरम्मत का उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी रेल मंत्री महोदय का एक पत्र आया है, जो उन्होंने वार-फुटिंग पर कार्य किया है, कोई 10-11 रेल लाइनें हमारी नष्ट हो गयी थीं, उन्होंने कोशिश की है वह फिर से चालू हो गई हैं। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जो सुझाव मैंने सरकार के सामने निवेदन किये हैं, उन सब सुझावों पर सरकार गौर करे तो पानी जो जीवन के लिए आवश्यक है, वह दुख का कारण न बनकर सुख का कारण, हरियाली का कारण और खुशहाली का कारण बन सकता है और हम अनाज का बफर स्टाक पैदा कर सकते हैं इन प्रदेशों में क्योंकि हमारी मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है बिहार की, बंगाल की, उत्तर-प्रदेश की। इस उत्पादन को हम बाहर भेजकर फारेन-एक्सचेंज भी अर्न कर सकते हैं और कभी जिन प्रदेशों में सुखाड़ हो तो वहा सहायता की गुंजाइश भी हम रख सकते हैं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Shri V. Ramanathan. seven minutes please.

SHRI V. RAMANATHAN (Tamil Nadu) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I am glad that you have given me an opportunity to speak a few words on the subject. The allocations made to the State Governments are being drastically eroded on account of the quantum of relief works that they have to undertake. The States are thus suffering for want of funds and are not able to manage the flood and drought situation in the country. Previously in different years while a few States were being affected by

floods in one year, a few others were being affected by drought in another year, but unfortunately for the past three years many parts are being affected by drought and many parts by floods every year. Due to continuous drought conditions during the past 3-4 years, the major portions of the country are suffering great losses. Even in the current year, as per the reports, the relief work due to failure of rains is expected to be of the order of Rs. 1600 crores and loss in production is expected to be around 15 million tonnes. Because of these losses in production, the GNP is going to be very much below normal. Loss in agricultural production may go up to Rs. 1000 crores. That is the estimate of the specialists. Power generation, due to shortage of rains, is also going to suffer and consequently the industrial production may also be affected. This climatic cycle affects one or the other country. Under these circumstances, we have to analyse the reasons and take remedial measures to combat flood and drought. We have to find out why we have floods almost every year in certain areas and we have drought in certain other areas and we have to find a solution, a long-term solution, to fight this problem. We cannot always expect rains to come according to our requirement. At the same time, we have to prepare ourselves to face these problems. We are not able to preserve the rain-water properly to most our needs during drought period. Our reservoirs and tanks are not properly maintained, which ultimately affects our agriculture. Ground water is being tapped to the maximum extent and lakhs and lakhs of wells are being dug for our agricultural needs and industrial requirements. We have to make an assessment of the availability of water under the ground and make efforts to utilise it in such a way that underground water level is maintained. Otherwise, we cannot save the situation if there is a drought. Therefore, maintaining ground water level is very important.

We have to take steps to improve underground Water level during rains. But we are not putting up check dams and not caring for proper storage of water. Earlier, there used to be a lot of waste land, uncultivated land which used to help in holding a lot of water by wild growth of trees. Now, for various reasons, all that waste land is being converted to agricultural land or house-sites. We find so much of deforestation which adds to our problems. If there are no trees, water-holding capacity of the land is lost. Then, we have the problem of soil erosion. Due to this, the rivers have risen. Silt clearance is not possible in the rivers and tanks. Therefore, there cannot be any storage of water. The rivers also dry up when there are no rains, and during rains so much of water is wasted away. As a result of this, the people who suffer a lot are only those who are at the tail-end of the river. As has been pointed out by my learned friend, it is the people at the tail-end of the river who suffer during floods. The people at the head of the river utilise the river water to the maximum extent possible leaving the people below with not much water. They do not have water for irrigation; they do not have water even for drinking purposes. Take, for example, a perennial river like Cauvery. The people of Tamil Nadu were benefited by it. Specially, Tanjore which is considered a granary of Tamil Nadu. The river in the Tamil Nadu portion is now almost dry. Many lands in Tanjore district are lying fallow. The Karnataka Government, on the other hand, is constructing a number of dams on the river. Now, they are constructing a fourth dam. Besides the objections raised by the Tamil Nadu Government, they are doing all this without the sanction of the Government of India.

SHRI K. G. MAHESWARAPPA (Karnataka) : Cauvery is not a monopoly of Tamil Nadu.

SHRI V. RAMANATHAN : It may not be a monopoly, but we have been utilising the water and our riparian rights cannot be taken away. For hundreds of years, the people of Tamil Nadu have been utilising the water for irrigation. They may say that it is not our right. But when floods come due to rains, it is the people of Tamil Nadu who are affected. Water from the top comes to the Tanjore delta and it affects the Tanjore-Trichy area. Crops which are raised by the toil of the people are washed away.

Sir, as I said, maximum utilisation of the rain water and augmentation of the ground water table are the most important things.

[V. Ramanathan]

Government should also evolve a national water policy ensuring that no State has a monopoly in regard to use of the water resources, even though a particular river may originate from a particular State. There should also be maximum and judicious utilisation of the rain water which will enable us to improve productivity and we can also avoid damage to crops and lands during floods. Government of India should bestow serious attention to this.

In this connection, I would like to draw the attention of the Government to the non-clearance of the Telugu Ganga project by the Centre. If this project is implemented, the drinking water problem of Madras will be solved. The two State Governments are prepared to get on with the project, but the Centre is not giving clearance. I would request the Central Government to give immediate clearance to this project so that the Madras city's drinking water problem can be solved.

श्री नत्था सिंह (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में जो बाढ और सूखे के ऊपर चर्चा हो रही है, उस पर अपने विचार प्रकट करने का आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

श्रीमन, देश के अनेक भागों में जहां बाढ़ से लोग प्रभावित हुए हैं, वहां देश के आधे से ज्यादा इलाकों में सूखा पडा हुआ है । मैं जिस राज्य से आता हूं राजस्थान से उस राजस्थान के बारे में थोडी सी सदन में चर्चा करूंगा ।

राजस्थान में 27 जिले हैं और 27 जिलों में सूखा पडा हुआ है। यह सूखे का असर वहां की जनता पर तकरीबन 3 करोड रुपए का पड़ा है। भारत सरकार ने हम को जो राशि दी है वह न के बराबर है। 29 करोड हमें दिया है, अनाज भी दिया है हम यह समझते हैं यह न के बराबर है।

अभी हमारे वक्ताओं ने राजस्थान के लिए और मध्य प्रदेश के लिए बात की है। दोनों ही प्रदेश महत्वपूर्ण हैं। मध्य प्रदेश सबसे बडा प्रांत है और एरिया के लिहाज से राजस्थान दूसरे नम्बर पर आता है । मैं आपको राजस्थान के बारे में बताना चाहता हूं कि अब तक चारे के बगैर और पानी के बगैर [illegible] ने व्यवस्था की है । राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी जी भी युद्ध स्तर पर सूखे का मुकाबला कर रहे हैं। फिर भी चारे बगैर, पानी के बगैर तकरीबन 25–30 मवेशी मर चुके हैं । अभी आपके सामने मेरे साथी बाघेला जी ने जो पड़ोसी राज्य से आते हैं उन्होंने बताया है वहां भी मवेशी मर रहे हैं। मैं आपको यह बताऊंगा कि राजस्थान में भी काफी मवेशी मर रहे हैं। इसके लिए समाज सेवी संस्थाएं, भारत सरकार, प्रधान मंत्री को मैं धन्यवाद दूंगा कि हिन्दुस्तान की बाढ और सूखाड का मुकाबला युद्धस्तर पर कर रहे हैं।

मैं यह भी कहूंगा कि राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर को स्पेशल बजट रख कर, ज्यादा पैसा अलग से देकर, पूरा करवा दिया जाये तो जोधपुर, बाडमेर, पाली, नागौर जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं वे बाढ का मुकाबला आसानी से कर लेंगे। दूसरे पूर्वी राजस्थान के लिए भी दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं । गंगा यमुना पर बांध लगवायें तो अलवर, सवाई माधोपुर, धौलपुर वे इलाके जो पूर्वी राजस्थान में हैं इनको फायदा मिलेगा। भारत सरकार उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य मंत्री से बातचीत करके पूर्वी राजस्थान को पानी दिलवाये। मेरा सुझाव यह है चम्बल का जो पानी आता है उसका हम 25 परसेंट ही रोक पाते हैं। ज्यादातर पानी चम्बल का उत्तर प्रदेश में चला जाता है । आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहूंगा कि चम्बल का 70, 75 परसेंट पानी जो उत्तर प्रदेश को चला जाता है उसको धौलपुर में बांध कर राजस्थान बार्डर पर लिफ्ट योजना से पानी पहुंचाया जा सकता है। राजस्थान में यानी पश्चिमी राजस्थान में 40–50 फुट कुए का पानी नीचे उतर गया है और पूर्वी राजस्थान में 15 फुट, 20 फुट तक पानी नीचे उतर गया है। मैं जिस जिले से आता हूं भरतपुर से वहां 20, 25 और 30 फुट तक पानी नीचे उतर गया है। जिन किसानों ने ट्यूब वैल लगा रखे हैं, जिन किसानों ने बिजली की मोटर लगा रखी है तो मोटर चलती है लेकिन पानी नहीं है। इसलिये इन कुओं को गहरा करने के लिये रोमानिया से जो मशीन आती है उनसे उनको गहरा किया जाय और जल्दी से जल्दी गहरा किया जाय। इसी तरह जहां पहाड़ी इलाके हैं जहां पीने के लिये पानी नहीं

आशा है कि इन बातों की ओर मंत्री महोदय विशेष ध्यान देंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि मैंने अभी दो-तीन दिन पहले, शनिवार और इतवार को मैंने अपने इलाके में टूर किया था। यहां पर जो कार्य हो रहे हैं जैसे सड़कों तथा नहरों का काम तो वहां पर जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनसे मैं मिला। मजदूरों से मैंने पूछा कि तुम्हें मजदूरी कितनी मिलती है तो उन्होंने कहा कि हमें 11 रुपये प्रति दिन मिलता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपने जो 14 रुपये प्रति दिन का प्रस्ताव रखा है वही पैसा इन मजदूरों को दिया जाय। जो मजदूर वहां अकाल राहत कार्यों में काम कर रहे हैं मैंने उनसे पूछा कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एम. पी साहब हमें एक दिक्कत है। हमें महीना हो गया है लेकिन हमें दो-दो हफ्ते, तीन-तीन हफ्ते तक पैसा नहीं मिलता है। इसलिये उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगा कि मजदूर जो हैं वे रोज खाते हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वे एक महीने तक अपनी भोजन की व्यवस्था कर सकें इसलिये आप ऐसी व्यवस्था करें ताकि उनको जल्दी-जल्दी मजदूरी मिल सके। मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि जो मस्टर रोल हैं उसको जल्दी से जल्दी चुकवाया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगा कि आज 16 नवम्बर है और अगले वर्ष 15 जुलाई तक बारिश आयेगी। हमें अभी आठ महीने अकाल से जूझना पड़ेगा। आठ महीने बड़ा लम्बा समय है। इसलिये इन आठ महीनों के लिये चारे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और अनाज की व्यवस्था जल्दी से जल्दी भारत सरकार को युद्ध स्तर पर करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, फिर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि राजस्थान को ज्यादा सहायता दी गई है, वाघेला साहब यह कह रहे थे तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पूरे राजस्थान का टूर करके वहां की हालत देखिये तब आपको पता चलेगा कि वहां की क्या हालत है। वहां राज्य सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है, पानी पहुंचा रही है, चारा पहुंचा रही है। यह सब राज्य सरकार कर रही है। लेकिन जो राज्य सरकार कर रही है वह ना के बराबर है। भारत सरकार जितना देती है उसी हिसाब से राज्य सरकार करती है। अभी हमें केवल 129 करोड़ रुपया मिला है। अब हमारी जो दूसरी मांग है वह एक हजार कुछ करोड़ रुपये की है। अगर यह धनराशि हमको जल्दी से जल्दी मिल जाये, अगर भारत सरकार यह सहायता शीघ्र देती है तभी राजस्थान इस सूखे का मुकाबला कर सकता है। महोदय, इतना ही कहकर, आपने मुझे सात मिनट का समय दिया था और मैं आठ मिनट बोला हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Shri Mohd. Khaleelur Rahman. Seven minutes, please.

PROF. C LAKSHMANNA (Andhra Pradesh) : It is a maiden speech, Sir. .. (*Interruptions*) . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : I think he had spoken once. earlier.

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA (Andhra Pradesh) : He only sought clarifications on that day This is a maiden speech.

श्री मुहम्मद खलील-उर-रहमान (आंध्र प्रदेश): महोदय, हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ प्रांतों में सूखा पड़ा है। कई जगह सूखा बारिश की वजह से है और इनमें राजस्थान और गुजरात का नाम खासतौर से लिया जा रहा है। कई जगहों पर बाढ़ की वजह से भी सूखा पड़ रहा है जैसे कि असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश वगैरह। इसमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट कहां तक अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रही है, इसके ताल्लुक से भी अब तक बहुत कुछ कहा जा चुका है। जहां तक सूखे का सवाल है इसको पोलिटिकल मसला बनाए बगैर इन्सानी बुनियादों पर इस नाजुक मसले को हल करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि सरकजी एकमत ने अगर अब तक ऐसा नहीं किया है तो आइन्दा से जरूर इस समस्या को इन्सानी बुनियादों पर हल करने की पूरी-

[श्री मुहम्मद खलील-उर-रहमान]
पूरी कोशिश करेगी। इसके लिए यह जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ पूरा-पूरा ताउन्न करना पड़ेगा तभी जा कर यह सूखे का मसला हल हो सकता है। अगर सिर्फ एक तरफा बात हो और कोशिश यह की जाए कि सिर्फ एकतरफा तरीके से इस मसले को हल करें तो यकीनन इसमें नाकामी होगी। इसी वजह से यह जरूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पूरे एतमाद में लिया जाए। इस वजह से कि प्रोग्राम और पालसियों को नाफिस करने वाली और किस जगह क्या सूरतेहाल है जिस अच्छे तरीके से रियासती हकूमतें जानती हैं मरकजी हकूमत उससे उतनी वाकिफ नहीं होती। इस वजह से यह जरूरी है कि रियासती हकूमतों को मुकम्मिल एतमाद में लिया जाए।

जहां तक हमारी रियासत आन्ध्र प्रदेश का सवाल है मैं यह कहूंगा कि सितमजरीफी यह है कि रियासते आन्ध्रप्रदेश मुल्क की वह वाहिद रियासत है जहां सूखा बारिश की कमी और बाढ दोनों वजह से पड़ा है। इसके बाज इलाकों में बारिश की शदीद कमी की वजह से सूखा पड़ा है और बाज इलाकों की सूरते-हाल बाढ की वजह से मुतासिर हुई है। जहां तक आंध्र प्रदेश का ताल्लुक है यह कहा जाता है कि वह पूरे मुल्क की अन्न-दाता है, पूरे मुल्क को चावल सप्लाई करती है गिजा सप्लाई करती है। इस रियासत में पिछले चार साल से मुसलसल सूखा पड़ा हुआ है जो यकीनन इन्तेहाई दुख और अफसोस की बात है। मैं इस सिलसिले में यह कहूंगा कि जब कभी मरकज से हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने नुमांइदगी की तो मुझे यह कहते हुए इन्तेहाई दुख और अफसोस होता है कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ तआव्वुन करना चाहिये था उसको असिस्ट करना चाहिये था उसको फायनेंशियल एड देनी चाहिये थी उस किस्म की बात नहीं हुई। इस सिलसिले में मुखतलिफ ताखीरी तरीके अपनाए गये। सेंट्रल टीम्ज को भेजा गया मगर सेंट्रल टीम्ज वहां पर आने के बाद जिस सही और गैर-जानिब्दार अन्दाज में वहां पर इस्पेक्शन करना चाहिये था वहां पर इन्क्वारी करनी चाहिये थी वहा के स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को साथ रखना चाहिये था बजाय इसके उन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों के साथ जिस जगह चाहा वहां पर गये और वहां से इन्क्वायरी करने के बाद आ गये और वहां की क्या रिपोर्ट दी गई है वह भी अभी तक हमारे सामने नहीं आई है और जो इमदाद मांगी गई थी वह इमदाद भी नहीं दी गई है। हमारे वजीरे आजम सूखे की सूरतेहाल का मुआयना करने श्रीकाकुलम और विशाखापटनम् डिस्ट्रिक्ट्स तशरीफ लाए जब रियासते आन्ध्र प्रदेश के अवाम को यह मालूम हुआ कि सूखे का मुआयना करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो उन में खुशी की लहर दौड़ गई। श्रीकाकुलम और विशाखपटनम के दौरे के वक्त जो नीति अपनाई गई वह इन्तेहाई अफसोसजनक है। वह यह कि हमारे इलाके में तेलगू बोली जाती है और प्राइम मिनिस्टर तेलगू नहीं समझ सकते। जब वो वहां पर गये तो लोगों के साथ बातचीत के वक्त उनको यह चाहिये था कि वह इशार्शियल मुतरजिम के जरिये से इन्टरप्रिटेशन हासिल करें। तरजुमे के लिए सरकारी ओहदेदारों की खिदमात हासिल की जा सकती थी बजाये इसके उन्होंने खुद उन्हीं की पार्टी के बाज शिकस्तखुर्दा लीडरों की खिदमात हासिल की। इत्तिहाई अफसोस की बात है कि तेलगू से अंग्रेजी में जान बूझ कर गलत तरजुमे की वजह से इस नाजुक खास मकसद के लिए जो चीज की जा रही है उसके बजाये जो वहां के कांग्रेस पार्टी के लीडर्स से चीफ मिनिस्टर की तकरार हो गयी और कुछ तल्ख कलामी हो गयी और इसमें मरकजी कैबिनेट के भी बाज जिम्मेदार मिनिस्टर शामिल हैं।

इस सिलसिले में एक बात और कहूंगा कि जब प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लाये तो क्या एक प्राइम मिनिस्टर का फर्ज नहीं होता है कि जिस स्टेट में वे जायें, जिस कार में वे घूमें अपने साथ उस रियासत के चीफ मिनिस्टर को भी रखें ताकि चीफ मिनिस्टर बता सके कि किस जगह की क्या सूरते हाल है। बजाय इसके उन्होंने चीफ मिनिस्टर को बैठाना गंवारा नहीं किया और उनकी मोटर कार से कोई तीन चार कार के बाद चीफ मिनिस्टर की मोटर कार थी। आप अंदाज लगाइये कि क्या इस तरह सूखे का मुआयना किया जा सकता है। एक सौ किलोमीटर फी घंटा की स्पीड के साथ खुद कार चलाते हुए क्या खेतों को देख सकते थे क्या फसलों को देख सकते थे। हो सकता है कि 10-15 दिन पहले कोई बारिश हुई हो जिससे वहां की घास हरीभरी हो गयी हो तो उनको देखकर समझना कि यहां सूखे की

सूरते हाल नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूं और न कोई पॉलिटिकल मसला बना रहा हूं ...(व्यवधान) मुझे आप बोलने का मौका दीजिए। कम से कम मुझे बोलने तो दीजिए।

मगर कम से कम इस किस्म की बात आइंदा नहीं होनी चाहिए। अभी तेलगु गंगा की बात आई। अभी मेरे दोस्त तमिलनाडु के मुअज्जिज मेम्बर तेलगु गंगा के मुतालिक बोल रहे थे। यह हमारी रियासत की और हमारे चीफ मिनिस्टर की ख्वाहिश है कि तेलगु गंगा प्रोजेक्ट जितनी जल्दी हो सके मुकम्मिल कर दिया जाये। लेकिन तमामतर कोशिशों के बावजूद तेलगु गंगा के प्रोजेक्ट को कोल्ड स्टोरेज में डालकर रखा गया है और क्लियरेंस नहीं दिया जा रहा है। यह तेलगु गंगा का प्रोजेक्ट मल्टी परपज प्रोजेक्ट है। हमारी स्टेट के रायलसीमा के बाज इलाके इस प्रोजेक्ट के जरिये सैराब हो सकते हैं। शहर मद्रास में पीने के पानी का मसला जो निहायत भयानक मसला बना हुआ है वह भी इसके जरिये हल हो सकता है। मगर इतने दिन होने के बावजूद, मुसलसल कोशिशों और नुमाइंदिगी के बावजूद भी तेलगु गंगा के प्रोजेक्ट को आज तक हल नहीं किया गया है। इसके अलावा और भी हमारी स्टेट के कई आबपाशी प्रोजेक्ट्स हैं। अचमपल्ली प्रोजेक्ट है, जोराला प्रोजेक्ट है, श्रीराम सागर प्रोजेक्ट है, वमसाधारा और अन्य प्रोजेक्ट्स हैं जो यहां पर इस वक्त क्लियरेंस के लिए इंतजार कर रहे हैं। मुझे पूरी तवक्को है कि मरकजी हुकूमत इस तरफ तवज्जह करके जल्द से जल्द हमारे इन प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस देगी। इस वक्त हमारे रियासते आंध्र प्रदेश में जुमला 18 इजला हैं जो सूखे और बाढ़ से मुतासिर हैं। जुमला मुतासिरा गाव के तादाद 53-51 हैं। 272 90 लाख आबादी मुतासिर हुई है। 34 लाख हेक्टेयर फसल का इलाका मुतासिर हुआ है। 142.86 लाख मवेशी मुतासिर हुए हैं। इसके लिए रियासती हकूमत से मरकजी हुकूमत से 546.50 करोड़ रुपये की इमदाद तलब की है। इन आदादओं शुमार का इनकिशाफ खुद मरकजी हुकूमत के वजीरे जराअत ने एक स्टार्ड क्वेश्चन के जवाब में 6 नवम्बर, 1987 को इसी इवान में किया है। मगर इसके बावजूद अब तक 68 करोड़ रुपया दिया गया है। आप ही अंदाजा लगाइये कि 546.50 करोड़ रुपये के मुकाबले में सिर्फ 68 करोड रुपये देने से क्या यह मसला हल हो सकता है। इससे इनकी प्यास भी नहीं बुझ सकती, उसका हलक भी तर नहीं हो सकता। इस वजह से जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी को पूरी न करे और उस रियासत में सूखे से जो मुत्तासिर हुए हैं ख्वा वे इन्सान हों कि मवेशी ख्वा फसलों की बात हो या पीने के पानी का मसला, जब तक कि फिराखदिलाना तौर पर और हकायक पर मबनी है। मुन्दरजा बाला आदादोशुमार को पेशेनजर रखते हुए जब तक कि आप इमदाद नहीं करेंगे, उस वक्त तक यह मसला हल नहीं हो सकता।

मैं ज्यादा तफसील में गये बगैर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि रियासते आन्ध्र प्रदेश एक जराती रियासत है और वहां की तकरीबन 50 फीसदी आबादी का पेशा जरात और पूरे मुल्क में चावल की काश्त में इम्तयाजी तौर पर पानी पहचानी जाती है।

लिहाजा इसको मजीद कोई नुकसान हुए बगैर ख्वा वह बाढ़ से हो या बारिश की कमी से हो, जल्द से जल्द रियासिती हुकूमत की जानिब से तलब की गई खातिरख्वाह और एडीशनल इमदाद जारी की जाए।

यह कहते हुए मैं जनाबे सदर का शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने मुझे इसके लिए वक्त दिया।

†[شری محمد خلیل الرحمان (آندھرا پردیش) : مہودے - ہندوستان کے مختلف پرانتوں میں سوکھا پڑا ہے - کئی جگہ سوکھا بارش کی وجہ سے ہے اور ان میں راجستھان اور گجرات کا نام خاص طور سے لیا جارہا ہے - کئی جگوں پر باڑھ کی وجہ سے بھی سوکھا پڑ رہا ہے - جیسے کہ آسام - بہار - اترپردیش - ویسٹ بنگال - اروناچل پردیش وغیرہ - اس میں سینٹرل گورنمنٹ کہاں تک اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہی ہے - اس کے تعلق سے بھی اب تک بہت کچھ کہا جا چکا ہے -

†[ ] Transliteration in Arabic script.

[شری محمد خلیل الرحمان]

جہاں تک سوکھے کا سوال ہے و اس پولیٹیکل مسئلہ بنائے بغیر انسانی بنیادوں پر اس نازک مسئلے کو حل کرنا پڑیگا اور امید کرتا ہوں کہ مرکزی حکومت نے اگر اب تک ایسا نہیں کیا ہے تو آئندہ سے ضرور اس سمسیا کو انسانی بنیادوں پر حل کرنے کی پوری پوری کوشش کرے گی اسکے لئے یہ ضروری ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ کو اسٹیٹ گورنمینٹ کے ساتھہ پورا پورا تعاون کرنا پڑیگا تبھی جاکرکے سوکھے کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اگر صرف ایک طرفہ بات ہو اور کوشش یہ کی جائے کہ صرف ایک طرفہ طریقہ سے اس مسئلے کو حل کریں تو یقیناً اسمیں ناکامی ہوگی اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اسٹیٹ گورنمینٹ کو بھی پورے اعتماد میں لیا جاوے اس وجہ سے کہ پروگرام اور پالیسیوں کو نافذ کرنے والی اور کس جگہ کیا صورتحال ہے جس اچھے طریقے سے ریاستی حکومت جانتی ہیں مرکزی حکومت اس سے اتنی واقف نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ریاستی حکومتوں کو مکمل اعتماد میں لیا جائے۔

جہاں تک ہماری ریاست آندھرا پردیش کا سوال ہے۔ میں یہ کہونگا کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ ریاست آندھرا پردیش ملک کی واحد ریاست ہے جہاں سوکھا بارش کی کمی اور باڑھہ دونوں وجہ سے پڑا ہے۔ اس کے بعض علاقوں میں شدید بارش کی کمی کی وجہ سے سوکھا پڑا ہے اور بعض علاقوں کی صورتحال باڑھہ کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے۔ جہاں تک آندھرا پردیش کا تعلق ہے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پورے ملک کی اندانا ہے۔ پورے ملک کو چاول سپلائی کرتی ہے۔ غذا سپلائی کرتی ہے۔ اس ریاست میں پچھلے چار سال سے مسلسل سوکھا پڑا ہوا ہے۔ جو یقیناً انتہائی دکھہ اور افسوس کی بات ہے۔ میں اس سلسلے میں یہ کہونگا کہ جب کبھی مرکز سے ہماری اسٹیٹ گورنمینٹ نے نمائندگی کی تو مجھے یہ کہنے انتہائی دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ جس طرح سے سنٹرل گورنمینٹ کو اسٹیٹ گورنمینٹ کے ساتھہ "تعاون" کرنا چاہئے تھا اسکو اسسٹ کرنا چاہئے تھا اسکو فائنینشیل اڈ دینی چاہئے تھی اس قسم کی بات نہیں ہوئی۔ اس سلسلے میں مختلف تاخیری طریقے اپنائے گئے۔ سنٹرل ٹیمز کو بھیجا گیا۔ مگر سینٹرل ٹیمز وہاں پر آنے کے بعد جس صحیح اور غیرجانبدار انداز میں وہاں پر انسپکشن کرنا چاہئے تھا وہاں پر انکوائری کرنی چاہئے تھی وہاں کی اسٹیٹ گورنمینٹ کے منسٹر کو ساتھہ رکھنا چاہئے تھا۔ بجائے اس کے انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کے ساتھہ جس جگہ چاہا وہاں پر گئے اور وہاں سے انکوائری کرنے کے بعد آگئے اور وہاں کی کیا رپورٹ دی گئی ہے وہ بھی ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی اور جو امداد مانگی گئی تھی وہ امداد بھی نہیں دی گئی ہے۔ ہمارے وزیراعظم سوکھے کی صورتحال کا معائنہ کرنے "سری کاکلم" اور "وساکھاپٹنم" ڈسٹرکٹ تشریف لائے۔ جب ریاست آندھرا پردیش کے عوام کو یہ معلوم ہوا کہ سوکھے کا معائنہ کرنے کے لئے ہمارے پرائم

منسٹر آرہے ہیں- تو ان میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی ''سری کاکلم،، اور ''وشاکھا پٹنم کے دورے کے وقت جو نہی اپنائی گئی وہ انتہائی افسوسناک ہے- وہ یہ کہ ہمارے علاقے میں تیلگو بولی جاتی ہے اور پرائم منسٹر تیلگو نہیں سمجھ سکتے - جب وہ وہاں پر گئے تو لوگوں کے ساتھ بات چیت کے وقت انکو یہ چاہئے تھا - کہ وہ اسٹرسل مترجم کے ذریعہ سے انٹر پریٹیشن حاصل کریں- ترجمہ کے لئے سرکاری عہدیداروں کی خدمات حاصل کی جاسکتی تھیں - بجائے اسکے انہوں نے خود انہیں کی پارٹی کے بعض شکست خوردہ لیڈروں کی خدمات حاصل کیں - انتہائی افسوس کی بات ہے کہ تیلگو سے انگریزی میں جان بوجھ کر غلط ترجمے کی وجہ سے اس نازک اور خاص مقصد کیلئے جو چیز کی جارہی ہے اس کے بجائے جو وہاں کے کانگرس پارٹی کے ایڈرس سے چیف منسٹر کی تکرار ہوگئی- اور کچھ تلخ کلامی ہوگئی اور اسمیں مرکزی کیبنیٹ کے بھی بعض ذمہدار منسٹر شامل ہیں-

اس سلسلہ میں ایک بات اور کہونگا کہ جب پرائم منسٹر تشریف لائے تو کیا ایک پرائم منسٹر کا فرض نہیں ہوتا ہے کہ جس اسٹیٹ میں وہ جائیں جس کار میں وہ گھومیں اپنے ساتھ اس ریاست کے چیف منسٹر کو بھی رکھیں- تاکہ چیف منسٹر بتا سکیں کہ کس جگہ کی کیا صورتحال ہے- بجائے اس کے انہوں نے چیف منسٹر کو بیٹھانا گوارا نہیں کیا اور انکی موٹر کار سے کوئی تین چار کار کے بعد چیف منسٹر کی موٹرکار تھی- آپ اندازہ لگائیے کہ کیا اسطرح سوکھے کا معائنہ کیا جا سکتا ہے- ایک سو کلومیٹر کی فی گھنٹہ اسپیڈ کے ساتھ خود کار چلاتے ہوئے کیا کھیتوں کو دیکھ سکتے تھے- کیا فصلوں کو دیکھ سکتے تھے- ہوسکتا ہے کہ دس- پندرہ دن پہلے کوئی بارش ہوئی ہو جس سے وہاں کی گھاس ہری بھری ہوگئیں ہو تو اسکو دیکھکر یہ سمجھنا کہ یہاں سوکھے کی صورتحال نہیں ہے- ایسا نہیں ہونا چاہئے - میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی کوئی پولیٹیکل مسئلہ بنارہا ہوں-———

''مداخلت،،——— مجھے آپ بولنے کا موقع دیجئے- کم سے کم مجھے بولنے تو دیجئے-

مگر کم سے کم اس قسم کی بات آئندہ سے نہیں ہونی چاہئے ابھی تیلگو گنگا کی بات آئی ابھی میرے میرے دوست تامل ناڈو کے معزز ممبر تیلگو گنگا کے متعلق بول رہے تھے- یہ ہماری ریاست کی اور ہمارے چیف منسٹر کی خواہش ہے کہ تیلگو گنگا کا پروجیکٹ جتنی جلدی ہوسکے مکمل کیا جائے - لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود تیلگو گنگا کے پروجیکٹ کو کولڈ اسٹوریج میں ڈالکر رکھا گیا ہے- اور کلیرنس نہیں دیا جارہا ہے- یہ تیلگو گنگا کا پروجیکٹ ملٹی پرپز پروجیکٹ ہے- ہماری اسٹیٹ کے رائل سیما کے بعض علاقے اس پروجیکٹ کے ذریعہ سیراب ہوسکتے ہیں- شہر مدراس میں پینے کے پانی کا مسئلہ

[شری محمد خلیل الرحمان]

جو نہایت بھیانک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ وہ بھی اس کے ذریعہ حل ہو سکتا ہے۔ مگر اتنے دن ہونے کے باوجود مسلسل کوششوں اور نمائندگی کے باوجود بھی نیلگو گنگا کے پروجکٹ کو آج تک حل نہیں کیا گیا ہے۔ اسکے علاوہ اور بھی ہماری اسٹیٹ کے کئی آبپاشی پروجکٹس ہیں - "اچم پلی پروجکٹ" ہے "پولاورم پروجکٹ" ہے - "سری رام ساگر پروجکٹ" ہے وسادھارا اور دوسرے پروجکٹ ہیں۔ جو یہاں پر اس وقت کلیرنس کیلئے انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے پوری توقع ہے کہ مرکزی حکومت اس طرف توجہ کرکے جلد سے جلد ہمارے ان پروجکٹس کو کلیرنس دیگی۔ اس وقت ہماری ریاست آندھرا پردیش میں جملہ ۱۸ اضلاع ہیں جو سوکھے اور باڑھ سے متاثر ہیں۔ جملہ متاثرا گاؤں کی تعداد ۱۰۵۳۰ ہے۔ ۹۰-۲۲۷ لاکھ آبادی متاثر ہوئی ہے۔ ۴۳ لاکھ ہیکٹر فصل کا علاقہ متاثر ہوا ہے۔ ۸۶-۱۴۳ لاکھ مویشی متاثر ہوئے ہیں۔ اسکے لئے ریاستی حکومت نے مرکزی حکومت سے ۰۵-۶۴۵ کروڑ روپئے کی امداد طلب کی ہے۔ ان اعداد و شمار کا انکشاف خود مرکزی حکومت کے وزیر زراعت نے ایک اسٹارڈ کوئیچن کے جواب میں ۶ نومبر ۱۹۸۷ کو اسی ایوان میں کیا ہے۔ مگر اسکے باوجود صرف اب تک ۶۸ کروڑ روپیہ دیا گیا ہے - آپ ہی اندازہ لگائیے کہ ۰۵-۶۴۵ کروڑ روپئے کے مقابلے میں صرف ۶۸ کروڑ روپیہ دینے سے کیا یہ مسئلہ حل ہوسکتا ہے۔ اس سے ان کی پیاس بھی نہیں بجھ سکتی۔ اس کا حل بھی تو نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے جب تک سینٹرل گورنمنٹ اپنی ذمیداری کو پوری نہ کرے اور اس ریاست میں سوکھے سے جو متاثر ہوئے ہیں۔ خواہ انسان ہوں کہ مویشی، خواہ فصلوں کی بات ہو کہ پینے کے پانی کا مسئلہ۔ جب تک کہ فراخدلانہ طور پر اور حقائق پر مبنی مندرجہ بالا اعداد و شمار کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب تک کہ آپ امداد نہیں کرینگے۔ اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔

میں زیادہ تفصیل میں گئے بغیر اتنا ضرور کہنا چاہونگا کہ ریاست آندھرا پردیش ایک زراعتی ریاست ہے اور وہاں کی تقریباً ۸۵ فیصد آبادی کا پیشہ زراعت ہے اور پورے ملک میں وہ چاول کی کاشت میں امتیازی طور پر جانی پہچانی جاتی ہے۔

لہذا اسکو مزید کوئی نقصان ہوئے بغیر خواہ وہ باڑھ سے ہو یا بارش کی کمی سے ہو جلد سے جلد ریاستی حکومت کی جانب سے طلب کیگئی خاطر خواہ اور ایڈیشنل امداد جاری کی جائے۔

یہ کہتے ہوئے میں جناب صدر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو انہوں نے مجھے اسکے لئے وقت دیا -]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Shri Bir Bhadra Pratap Singh.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH (Uttar Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, Sir,. . . . .

PROF. C. LAKSHMANNA : In any case we can adjourn at 6 O'clock.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : According to the decision of the Business Advisory Committee the House can sit beyond 6 O'clock. What is the difficulty ?

PROF C LAKSHMANNA : It is a very important subject and should be understood by everybody. It can only be done when there is time.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : यह तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने छह बजे तक का टाइम दिया है। तो छह बजे तक चलाइये।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : नहीं ऐसी बात नहीं है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने ऐसा डिसाइड किया है कि अगर काम हो. . . .

श्री वीरेन्द्र वर्मा : एकाध आदमी कोई होता, तो ठीक है, खत्म हो जाता।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : That is the decision of the Business Advisory Committee. Even after 6 O'clock if the House desires we can sit.

PROF. C. LAKSHMANNA : If such an important subject has to be discussed it should be discussed only when the full House is there. What is the point in discussing it now?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : It is the decision of the Business Advisory Committee.

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA : When the discussion is going on, tomorrow also we can have it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Let him speak. (*Interruptions*).

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB) : Mr. Vice-Chairman, Sir, there are a large number of speakers from both sides. So far we have not taken up any Government business in this House. So, last time when the Business Advisory Committee met, we made it very clear and it was resolved that we would sit beyond 6 O'clock if required. There are some Members here who are prepared to speak now; let them speak; otherwise we will not be able to reach anywhere.

PROF. C. LAKSHMANNA : Why rush it through especially at this time of the hour?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : What is the difficulty? I am not able to understand. When other Members spoke the same number of Members were there. So we can continue. Let us accommodate as many Members as possible.

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA . If we are going to conclude the debate today, it is all right.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : No, no. There are three more speakers who are going to speak now.

SHRI M. M. JACOB : It is not fair. (*Interruptions*). When the hon. Member got up even before 6 O'clock you have blocked him.

6.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Mr. Reddy, please cooperate with me Those who are present today and want to take part in the debate, they can speak and those who are present but do not want to take part in the debate today, they can take part tomorrow.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh) : It will be a one-sided debate if debate is continued. From this side, there is no other speaker in the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : They will speak tomorrow. So far as Opposition is concerned, all those Members whose names are there will speak. As regards Congress (I), There Chief Whip will decide according to the time available.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Four Ministries are vitally concerned with the question under discussion, the Ministry of Agriculture, the Ministry of Planning and the Ministry of Finance, but the most important Ministry which is concerned with it is the Ministry of Water Resources both for the purpose of drought and floods. Unfortunately, that Minister was not visible throughout the debate and Mr. Vice-Chairman, Sir, I wish to pray through you without him, nothing can be done either with regard to floods or with regard to drought. Now, it is correct that certain portions of the land are under-

[Shri Bir Bhadra Pratap Singh]

severest drought and drought is continuing in so many parts of the country. It is also a fact that certain parts of the country were under flood but there are certain parts of the country where first there was drought and subsequently there was flood Now may I add one thing more to that that recently there was a cyclone which started from Orissa and it covered a good portion of Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Orissa, and so many States were under the devastating effect of that cyclone with the result that the sugarcane crops were razed to the ground, arhar crops were razed to the ground, paddy crops were razed to the ground and tremendous harm was done to it. So these four problems are the basic problems but my question is—what shall be the role of Ministry of Water Resources with regard to the floods and drought? Now the other day there was a question and two speakers mentioned it today that agriculture has suffered but industrial target would be achieved. I seriously contest this contention When agriculture has been affected this year if the Ministry of Planning or the Ministry of Agriculture function properly, we can make good the loss by next year but my contention is that the industry is going to suffer for five years to come and I think our target has been much hampered. I will give my reason later on. Now so far as drought is concerned, three reasons have been assigned. Firstly, what Mr. Nirmal Chatterjee has said that certain people want to make capital and they go to the extent of resorting to deforestation. Then also another hon. Speaker has referred to some hot steam flowing which was responsible for upsetting the rains and there was a drought. But the third reason is also very important. We are told that the monsoon that started from the Bay of Bengal has crossed to China for some time till it reverted back during the drought conditions in the country. *(Interruptions)*. Now, Mr. Vice-Chairman, Sir, if I do not get your attention as well as the attention of the two Ministers, I feel discouraged in speaking.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Mr. Minister, he wants your ears to what he speaks.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH : Now to my mind, the drought is mainly a question related to the utilisation of underground water resources in the country. Why do I say utilisation of underground water resources? Yesterday, I was in a village in The Prime Minister's constituency. When the canal is flowing water level has gone up. When there was no rain for one and a half months, water level had gone so down that the crops became useless. So the long term task is to tackle such exigencies when rains do not shower in time or when they fail for a month or two. Under such circumstances, what shall be the Government's underground water policy? I am reminded of 1947 when we were students and working under Shri J. C. Kumarappa. When I am talking of underground water policy, I am reminded of what he said. He said, "We are resorting to pumping out water from below to the top. A time will come when the upland will go dry and lose fertility."

SHRI G. S DHILLON : I am very grateful to Khaleelur Rahmanji and Satyanarayanji for being present. Only three Members on the other side are present I am so grateful to them. They should not go now and should listen to the Member who is speaking.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH : So my precise question is, what exactly are they going to do about the underground water level in this country? There should be a long-term policy concerning this question. Long-term policies must be considered seriously by the Minister of Water Resources. When I asked a question on 12th here, the hon. Minister was laughing. On 14th there was a conference which has reiterated what exactly I asked on that day. May I enumerate in brief? Essential sectors like drinking water, irrigation, electricity generation—macro, mini and large—and floods should be taken proper care of. There should be no land left barren without irrigation There are also the problems of seepage and alkalinity.

An hon. Member referred to the linking of the rivers of north and south. A national water policy to link the rivers of north and south was talked about even at the time of the First Five-Year Plan. Even after forty years, we are only talking of it It was mooted by Nehruji. What happened to that plan? When the north

is suffering from floods, the south is affected by drought. You should not isolate north from south. The linking of northern and southern rivers by canals must be undertaken. There was a conference on National Water Policy on the 14th and all these questions were considered at this conference. But what would be the effect of this drought and the floods in our country on the national economy? First of all, the drought in the country has created an increase in direct expenditure to the tune of about one thousand crores of rupees. Now, what is the result of this? There has been an increase in the Income-Tax surcharge to the tune of five per cent. There has been extra levy on hotel rooms and foreign tickets carry a surcharge. But the greatest casualties are the on-going schemes. With the increase in expenditure of one thousand crores to fight the drought, the on-going schemes would be the most affected. Every State is demanding four thousand crores or five thousand crores and I do not know what the criterion is to make such demands when everything is unplanned with one thousand crores of rupees more in expenditure to fight out the drought. These on-going schemes would be the worst sufferers and all the future schemes would be shelved. I will now tell you how the industry in the country will suffer. Industry would suffer because the Plan expenditure would be affected and industrial development is bound to be hampered. Now it will lead to lack of nourishment, reduction in efficiency and productivity in the rural sector.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Mr. Singh, you have taken already fifteen minutes. Please conclude now in two minutes.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: What I am trying to argue is ..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : I know you can argue very well. But the time is very short and that is the problem.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: What I am trying to argue is that this will have a multiplier effect. So, it is not correct to argue that industry would not be affected. I am trying to drive towards that conclusion. Now, the consumers' buying power would be decreased resulting in reduction in industrial production because of a decrease in demand and the automatic result would be lesser tax collection and the industrialists and the manufacturers would be paying less. So, it will naturally lead to lay offs and the industrial workers' buying capacity would be reduced.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Mr. Singh, the time is very limited. But the subject you are talking on will take much time.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH : Not very much. But I will take just two or three minutes more. Reduction in wages or income will lead to lesser and lesser demand for consumer goods. Rural people will migrate to cities creating various problems. But the most important, the most serious, effect would be this: Because of the rural conditions being bad, there is less demand for bullions in the rural areas. I am posing a question now to the Ministry of Finance. The price of silver has gone up by Rs. 500 per kg. The rural people's purchasing power has disappeared because of the floods and drought. How is it that the price of bullion is increasing? The only reason can be that the urban population has the least trust in our currency notes and so, the urban people are purchasing these bullions. So, it is not correct to say that this will have no effect on industry. I can tell you that after five years, our industrial targets would be affected very much. Thank you, Sir.

श्री भंवर लाल पंवार : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मानसून भारतवर्ष में जब जून से प्रारम्भ होता है तो पूरे राष्ट्र में मानसून की आशा होती है। इस वर्ष भारतवर्ष के 35 मैटीरियोलाजिकल डिवीजंस में से जब हमने देखा कि जून से लगातार 12 अगस्त तक जो स्थिति मानसून की रही व प्रधान मंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जब देश का यह आह्वान किया कि इस शताब्दी का सबसे भीषण महानतम जो अकाल है उसका बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़े साहस के साथ हिम्मत से हमें मुकाबला करना है, उन्होंने यह संकल्प लिया अपने विपुल अनाज के भंडार के परिप्रेक्ष्य में कि हमें इस चुनौती को झेलना है और झेलकर उन्होंने एक राष्ट्रीय सूखा राहत समिति का

□[**श्री भंवर लाल पंवार**]
गठन किया और हमने देखा कि प्रधान मंत्री जी के आह्वान पर स्वयंसेवी संस्थाओ एवं राष्ट्र ने और सरकार ने एक नीति निर्धारित की, एक कार्यक्रम तैयार किया और उसका अमल करना आरंभ किया, तब भारत की जनता को आशा बंधी कि जब स्वयं प्रधान मंत्री जी ने संकल्प लिया है कि इस राष्ट्र के महानतम अकाल की स्थिति को बड़ी हिम्मत के साथ झेलेंगे तो जनता भी साथ लगी और प्रधान मंत्री जी के आह्वान पर स्वयंसेवी संस्थाए भी आगे आई। स्वयंसेवी संस्थाओं ने इतना काम किया कि उसकी अगर मिसाल आप देखना चाहें राजस्थान और गुजरात में जाइए। भारत सरकार ने और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने 15 अगस्त के प्रधान मंत्री जी के लालकिले की प्राचीर से भाषण के पश्चात 17 अगस्त को "ड्राउट आफ 1987" की बेसिक इन्फर्मेशन के रूप में एक पुस्तिका प्रसारित की, उससे यह स्पष्ट है कि राजस्थान और गुजरात ही सबसे ज्यादा प्रभावित ड्राउट एफेक्टेड एरियाज हैं।

श्रीमन्, राजस्थान के संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पुस्तिका में जो वर्षा की फिगर्स दी गई हैं उसमें 66 प्रतिशत से 99 प्रतिशत लिखा है, सौ प्रतिशत नहीं लिखा है, लेकिन यह 99 प्रतिशत अंकित करता है कि राजस्थान सबसे ज्यादा सूखे से प्रभावित प्रान्त है।

मान्यवर, यह बात इससे भी प्रकट होती है कि राजस्थान के कुल 38129 गांवों में से सब के सब प्रभावित हुए, 27 के 27 जिले प्रभावित हुए और उस प्रान्त के जो मवेशी हैं करीब साढे तीन करोड़, उनकी हालत को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि स्वयंसेवी संस्थाए जो हमारी हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। मारवाड अकाल राहत समिति इस प्रकार से लाखों मवेशियो को करीब 46 अलग-अलग कैंपों में कैटल कैंपों में रखा और एक एक कैंप में 10 हजार कम से कम मवेशी हैं जिनका वह संरक्षण कर रहे हैं और एक अद्वितीय कार्य दूसरो को प्रेरणा देने के लिए वहां पर किया जा रहा है। रोज करीब-करीब 7 से 10 लाख के करीब जानवरों के लिए बाहर से चारा मंगा रही है मारवाड अकाल राहत समिति वहां पर पानी की व्यवस्था कर रही है। लाखो रुपए का परमेनेंट इंवेस्टमेंट कर कुंओ से, ट्यूब-वेल्स से खोदकर पानी निकालकर उन मवेशियो को पाल रही है। इस प्रकार की व्यवस्था करने में अगर स्वयंसेवी संस्थाए आगे नही आती तो देश आज परमात्मा द्वारा किए गए इस प्रकोप का सामना किस प्रकार से करता क्योंकि स्वयं सरकार की सीमाए होती है, उससे अधिक सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मैं इस सभा के माध्यम से भारत की पूरी जनता को आह्वान करना चाहूंगा कि जो कमाने वाला आदमी है इस अकाल को झेलने के लिए, इस बाढ़ की समस्या को झेलने के लिए अपने प्रतिदिन की आय में से 25 पैसे निकाले तो मैं सोचता हूं कि हम इस समस्या से निपट सकेंगे।

जैसा कि बेसिक इन्फरमेशन में दर्शाया गया है कि क्राप प्रोडक्शन, एम्पलायमेंट जिनरेशन, फोडर, पावर, इरीगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, सप्लाई आफ एसेन्शियल कमाडिटीज इत्यादि की कई योजनाओं को हाथ में लेकर इनका क्रियान्वयन प्रारम्भ किया है इससे जनता को रिलीफ मिला है, राहत मिली है।

इस समय शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलैस फार्मर्स, स्माल फार्मर्स इतनी भीषण समस्या में हैं कि अगर उनकी पूरी मदद नहीं की जायेगी तो बहुत ही विकट समस्या उत्पन्न हो जायेगी। मैं राजस्थान के सम्बन्ध में इस सदन के माध्यम से कृषि मंत्री जी को और भारत सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान पिछले 4 साल से अकाल से ग्रस्त हो रहा है। जब 86-87 कम्पलीट हुआ था उस समय भी आप जानते हैं राज्य का 36 करोड़ वेजेज के लिए एवं मेटिरियल कम्पोनेन्ट के लिए 46 करोड रुपये देना बाकी था। 82 करोड रुपया 86-87 में पेंडिंग था और अब अप्रैल से 87 तक आपके द्वारा 119 करोड रुपया दिया गया है। एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो राशि दी जा रही है एन. आर. ई. पी. या दूसरी स्कीमो में राशि को देते समय मेटिरियल कम्पोनेन्ट के लिए सीमित राशि दी है। मसलन एक व्यक्ति को बैठने के लिए एक बडी कार तो दी लेकिन अगर उसमें पैट्रोल का प्रावधान नही किया तो कार दी हुई कारगार नहीं होगी। यही हालत अब राजस्थान की हो रही है। पिछली जो अकाल की मीटिंग हुई थी उसमें हम पहुंचे थे। वहां अकाल राहत मंत्री जी से जब पूछा

गया तो उन्होंने बताया कि 100 करोड़ रुपया अनएक्सपेंडेड पड़ा है। पड़ा क्यों है? इसमें मेटीरियल कम्पोनेंट की राशि बहुत ही कम है। प्रधान मंत्री जी का आह्वान है कि आजकल जो भी कार्य किया जाये टम्पोरेरी काम न किये जाय, स्थायी, पक्के निर्माण के कार्य किये जायें। हालत यह है कि बगैर मेटीरियल कम्पोनेंट की राशि के वह काम पूरे नहीं हो पायेंगे। मैं सोचता हूं इसी कारण आपके द्वारा दिया हुआ अमाउंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया हुआ अमाउंट अनएक्सपेंडेड पड़ा है। मंत्री जी जरा इस ओर आप ध्यान दीजिए। यह देखिये कि इस समस्या का निवारण कैसे हो सकता है।

श्री रामानन्द यादव : यही तो रोना है कि आपकी सरकार खर्च नहीं करती है।

श्री भंवर लाल पंवार : मैं खुद ही कह रहा हूं कि 100 करोड़ रुपये अनएक्सपेंडेड पड़े हैं। क्यों पड़े हैं यह भी मैंने बताया है।

श्री रामानन्द यादव : आपने खुद ही बता दिया नहीं तो यह थैंकलैस जाब हमें करना पड़ता।

श्री भंवर लाल पंवार : जो फैक्ट्स हैं मैंने वही बताया। मैं यह कह रहा हूं कि मेटीरियल कम्पोनेंट के लिए राशि आप को अलग से देनी पड़ेगी तभी यह काम होगा।

श्री रामानन्द यादव : सारा सामान दे दीजिए तो लेबर को कुछ नहीं देंगे?

श्री भंवर लाल पंवार : जो आपने एन. आर. ई. पी. के लिए फंड दिया है वह रोड पर केवल धूल उड़ने के काम आ रहा है। लेबर को पेमेंट की जा रही है। लेबर को पेमेंट इस तरह से कर दी जाए, धूल उड़ाना आपको पसन्द है तो कोई काम आगे नहीं होने वाला है। अगले साल फिर वही होने वाला है जो अब हो रहा है। इसके साथ ही एक निवेदन और करना चाहता हूं। पिछले साल हमारी जिस प्रकार से आपने धान देकर सहायता की थी, रुपया हमें नहीं चाहिए, हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमें आप धान दीजिये। धान से हमारे डबल काम होगा। जो 11 रुपये की मजदूरी है आप जिस रेट से धान देते हैं तो इससे उसका 20 रुपये का काम हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वहां पर काम पूरा होने वाला नहीं है। इस ओर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : Now you please conclude.

SHRI B L. PANWAR . I am just giving a few facts, Sir.

मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन और करना चाहूंगा। राजस्थान सरकार की कार्य करने की प्रणाली क्या है यह मेरे भी समझ में पूरा नहीं आ पाया है। पिछले साल जब यह निर्णय कैबिनेट स्तर पर लिया गया था कि जवाई बांध की साइड में जो जिला जोधपुर, पाली, जालोर और बाड़मेर जिले हैं इनमें जोधपुर और पाली जिलों के लिये पानी की व्यवस्था जवाई बांध से स्थायी तौर से है। पिछले साल दो हजार एम. सी. एफ टी. पानी सिंचाई के लिये दे दिया। बावजूद इसके कि निर्णय लिया गया था कि नहीं दिया जायेगा। अगर नहीं दिया जाता तो यह पानी की भीषण समस्या जिसका मुकाबला करने के लिये आप करोड़ों रुपया टैंकर और रेलों द्वारा, 25 हजार लिटर के टैंकरों से पानी ला रहे हैं, तीन गाड़ियां तैयार की हैं इस पर जो खर्च किया है यह नहीं करना पड़ता। अगर इतना पानी पिछले साल इस तरह से वेस्ट न किया जाता तो पूरे साल के लिये वह 2 हजार एम. सी. एफ. टी. पानी जोधपुर और पाली जिले के लिये पर्याप्त होता और वहां पर पेय जल की समस्या उत्पन्न न होती। इसलिये इसके कार्यान्वियन के लिये आपको ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भी ध्यान देना होगा। राजस्थान कैनाल के पानी को जोधपुर लाने के संबंध में सन् 83 में प्रधान मंत्री जी जब महामंत्री थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि दो साल में जोधपुर में पानी राजस्थान कैनाल से पहुंचेगा। लेकिन उसके बाद डेढ़ साल तक उस कार्य को प्रारम्भ नहीं किया गया। जब ज्यादा जोर पड़ा तो फिर प्रारम्भ हुआ। लेकिन उसके बाद उसकी कार्य प्रणाली में पता नहीं किस प्रकार से परिवर्तन होते रहे और आज तक उस कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई। अब स्थिति यह है कि मदसर से बाप तक 40 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें उन्होंने कान्ट्रैक्ट दिया है। एक-एक, डेढ़-डेढ़ किलोमीटर का। उसके बाद बाप से

Shri B. L. Panwar

फलूदी तक 30 किलोमीटर का एरिया है उसके लिये भी टैंडर चल रहे हैं। फिर फलूदी से जोधपुर की 130 किलोमीटर की लाइन है। पता नहीं यह लाइन किस तरह से जोधपुर पहुंचेगी। अभी जिस तरह से कार्य किया जा रहा है राजस्थान सरकार द्वारा, उस हिसाब से देखा जाय तो इस पर 6 साल लगेंगे। जोधपुर की जनसंख्या में एक तिहाई मिलेट्री है। मिलेट्री वाले स्वयं कह रहे हैं कि इस काम को हम भी करने के इच्छुक हैं। अगर कहें तो हम इसको शीघ्र से शीघ्र पूरा कर सकते हैं। इसलिये इस ओर भी आप कृपया सोचकर इस कार्य को जल्दी से करायें, यह भी मेरा आपसे निवेदन है। (व्यवधान)...

इसके अलावा जोधपुर के लिये जो 120 लाख लिटर पानी चाहिए उसमें से लगभग आधा, दो दिन से एक दिन तो पानी कर दिया और 90 लाख गैलन कर दिया है। लेकिन यह भी फरवरी तक होगा क्योंकि जवाई बांध डेड स्टोरेज पानी था और केवल 30 नवम्बर तक ही पानी आयेगा उसके बाद नहीं आयेगा। वहां ड्रिलिंग हो रही है और अब स्थिति यह है कि मनाई, रामपुरा में खुदाई हो रही है बीजवाडिया गगघणे में खुदाई हो रही है रणसी गाव में हो रही है। इसमें स्थिति यह है कि लोकल लोग इतना रीजेंट कर रहे हैं कि जब गवर्नमेंट की रिग्स वहां जाती है, डिपार्टमेंट के आदमी वहां जाते हैं तो वह बगैर खोदे वापस आ रहे हैं। फोर्स को साथ लिये बगैर यह काम पूरा नहीं होगा। अगर यह काम महीने, दो महीने में पूरा नहीं होगा तो जोधपुर की जनता त्राहि त्राहि करने लगेगी। आलटरनेटिव अरेंजमेंट पानी का जो रेल के द्वारा करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल में अभी दो दिन में एक बार पानी मिलता है फिर छः दिन में एक बार पानी पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। जैसी अभी हमारी जो डिमांड चल रही है। अभी 434 करोड के अगस्त में 129·14 करोड़ आपने अभी जुलाई तक के लिए ग्रांट किया है और इसके इलावा अभी जुलाई से नेक्स्ट मार्च तक जो प्रोपोजल है वह भी आपके पास है जो 1035 करोड के लिए है। उसके सम्बन्ध में अगर जल्दी से निर्णय नहीं किया गया तो यह सभी चीजें पूरी नहीं हो पायेंगी। वर्ल्ड बैंक ने भी सूखा राहत के सम्बन्ध में यहां आकर देखा है तो उन्होंने भी ऋण देने की जो घोषणा की है उसके लिए भी जल्दी से केन्द्र सरकार के माध्यम से कार्यवाही को पूरा करें। एक निवेदन मैं करना चाहूंगा। मन्त्री जी आप लोग जब प्रधान मंत्री जी आ कर के सारा जायजा ले कर गये हैं जब हमारे प्रभारी मन्त्री टाईटलर साहब दो दो दफा वहां पधारे हैं और जायजा लेकर गये हैं सारी बातों को आपने देख लिया है और सारे प्रोपोजल ले लिए हैं ठीक समझे हैं उसके बाद भी आपने फिर 13 आदमियों का एक दल भेजा है 9 तारीख को तो वह अपने ढंग से देखेंगे पता नहीं किस प्रकार से देखते हैं। आप उन्हीं पर यदि आधारित होकर के इस समस्या को सुलझाना चाहेंगे तो वह कभी पूरा नहीं हो पाएगा ऐसे मामले को पोलिटिकल रूप में भी और एक केन्द्रीय सरकार के बड़े मंत्री के रूप में भी फाइनल डिसीजन लें और ब्यूरोक्रेट्स के आंकड़ो पर निर्भर न रहें। पूरी सहायता दिये बगैर राजस्थान का उद्धार होना मुश्किल है। (समय की घंटी) बस समाप्त कर रहा हूं। आपकी अनुदान के संबध में हमेशा यह नीति रही है कि जनसंख्या के आधार पर अनुदान दिया जाता है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र कितना बड़ा है जनसंख्या तो बिलकुल कम है। तो गाडगिल फार्मूले के आधार पर अनुदान देने वाली प्रक्रिया बन्द कीजिये और उस में भी सन् 1971 के जनसंख्या के आंकडों को आप आधार मान रहे हैं उसको यदि करना है तो 1981 की जनसंख्या के आधार पर कीजिए। अब तो 1991 आने वाला है इसलिए उसको भी आप दुरुस्त कीजिये। श्रीमन् राजस्थान में अरावली पर्वत का क्षेत्र भी है और मरु क्षेत्र भी है इसलिए दोनों फायदे राजस्थान को मिलने चाहियें। प्रधान मन्त्री जी की जिस प्रकार से पहाडी क्षेत्रों के प्रति नीति है उस हिसाब से राजस्थान को डबल फायदा दिया जाना चाहिये। अगर राजस्थान को इस प्रकार से सहायता दी गई तो राजस्थान प्रगति के पथ पर आ सकता है वरन् नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : The House stands adjourned till 11 a.m. tomorrow, the 17th November, 1987.

The House then adjourned at thirtyfour minutes past six of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 17th November, 1987.